सूचना का अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–4
(PART-2)
वर्ष 2011–12 से 2016 तक

निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या/आदेश संख्या/दिनांक	विषय	पृष्ठ सं0
1.	पत्रांक/रा0प0का0/2655/लेखा-2(ध0अ0)/2013-14 दिनांक 28 फरवरी, 2014	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद राज्य परियोजना कार्यालय ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग रायपुर देहरादून।	1
2.	पत्रांक/रा0प0का0/2913/लेखा-2(ध0अ0)/2013-14 दिनांक 31 मार्च, 2014	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद राज्य परियोजना कार्यालय ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग रायपुर देहरादून।	2
3.	पत्रांक/रा0प0का0/1314/लेखा-2(ध0अ0)/2013-14 दिनांक 09 अगस्त, 2012	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद राज्य परियोजना कार्यालय ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग रायपुर देहरादून।	3
4.	पत्रांक/रा0प0का0/919/लेखा-2(ध0अ0)/2013-14 दिनांक 29 जून, 2011	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद राज्य परियोजना कार्यालय ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग रायपुर देहरादून।	4
5.	पत्रांक/रा0प0का0/1227/लेखा-2(ध0अ0)/2016-17 दिनांक 8 नवम्बर, 2016	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद राज्य परियोजना कार्यालय ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग रायपुर देहरादून।	5
6.	पत्रांक/रा0प0का0/559/लेखा-2(ध0अ0)/2012-13 दिनांक 28 मई, 2012	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद राज्य परियोजना कार्यालय ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग रायपुर देहरादून।	6
7.	No.F.10-4/2013-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy 7811 6/8/13 Shastri Bhawan New Delhi Dated- 22nd July, 2013	ADDENDUM	7-8
8.	पत्रांक/रा0प0का0/1770/लेखा-2(ध0अ0)/2015-16 दिनांक 19 नवम्बर, 2015	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद राज्य परियोजना कार्यालय ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग रायपुर देहरादून।	9
9.	No.F.10-5/2013-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy New Delhi the 6th May, 2013	Release of Ist tranche of Ist installemnt of Cental share under SSA for the year 2013&14(Plan) to SSA, Uttarakhand	10-20
10.	No.F.10-2/2015-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy New Delhi the 25th August, 2015	Release of balance Ist Installment of Central share under SSA for the year 2015-16 to SSA Uttarakhand.	21-32

11.	No.F.10-3/2014-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy EE.14 Section New Delhi the 7th October, 2014	Release of balance of 1st Installment of grants under SSA for the year 2014-15 to SSA, Uttarakhand.	33–38
12.	No.F.10-3/2014-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy EE.14 Section New Delhi the 21st May, 2014	Release of ad-hoc (First) installment of grants under SSA for the year 2014-15 to SSA Uttarakhand	39–44
13.	No.F.10-5/2014-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy New Delhi the 6th May, 2013	Release of 1st tranche of Ist istallment of Central share under SSA for the year 2013-14(Plan) to SSA, Uttarkhand.	45–49
14.	No.F.10-5/2014-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy New Delhi the 5th November, 2012	Release of 2nd installment of Central share under SSA for the year 2012-13 (Plan) to SSA, Uttarakhand.	50–54
15.	पत्रांक संख्या 701/XXIV(1)/2012–03/2012 शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनांक 14 सितम्बर, 2012	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की स्वीकृति के संबंध में।	55–57
16.	पत्रांक संख्या 1000/XXIV(1)/2012–03/2012 शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनांक 07 दिसम्बर, 2012	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम संचालन हेतु केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	58–60
17.	No.F.10-5/2013-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy New Delhi the 6th May, 2013	Release of 1st tranche of Ist installment of Central share under SSA for the year 2013-14 (Plan) to SSA, Uttarakhand.	61–64
18.	No.F.10-5/2013-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy New Delhi the 27th March, 2014	Release of 4th installment of Central share under SSA for the year 2013-14 (Plan) to SSA, Uttarakhand.	65–69
19.	पत्रांक संख्या 1113(i)/XXIV(1)/2013–16/2013 शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनांक 06 दिसम्बर, 2013	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	70–72
20.	पत्रांक संख्या 365/XXIV(1)/2014–16/2013 शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनांक 20 मार्च, 2014	वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए सर्व शिक्षा योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	73–74

21.	No.F.10-3/2014-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy EE.14 Section New Delhi the 23rd May, 2014	Release of ad-hoc (first) installment of grants under SSA for the year 2014-15 to SSA, Uttarakhand.	75-77
22.	No.F.10-3/2014-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy EE.14 Section New Delhi the 7th October, 2014	Release of balance of 1st installment of grants under SSA for the year 2014 -15 to SSA, Uttarakhand.	78-79
23.	पत्रांक अर्थ-2/17053-60/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 01 दिसम्बर, 2014	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अवमुक्त प्रथम किश्त के साथ राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	80
24.	पत्रांक संख्या 1221/XXIV(1)/2014-11/2014 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 29 नवम्बर, 2014	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अवमुक्त प्रथम किश्त के साथ राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	81-85
25.	पत्रांक अर्थ-2/5933-39/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 27 जून, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	86-89
26.	No.F.10-5/2014-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy EE.14 Section New Delhi the 24th May, 2011	Release of ad-hoc grants under SSA for the year 2011-12 (Plan) to SSA Uttarakhand.	90-94
27.	पत्रांक अर्थ-2/123-30/5क(01)03/2011-12 दिनांक 19 नवम्बर, 2011	मध्यान्ह भोजन योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	95-97
28.	पत्रांक संख्या 1104/XXIV(1)/2011-29/2011 शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 15 नवम्बर, 2011	मध्यान्ह भोजन योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	98-100
29.	No.F.10-5/2011-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy New Delhi the 24th May, 2011	Release of ad-hoc grants under SSA for the year 2011-12 (Plan) to SSA Uttarakhand.	101-111
30.	No.F.10-5/2012-E.E.14 Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy New Delhi the 11th July, 2012	Release of 2nd trench of Ist intallment of Central share under SSA for the Year 2012-13 (Plan) to SSA, Uttarakhand	112-116

"उत्तराखण्ड सभी के लिे शिक्षा परिषद"
राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग रायपुर देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2781941 2781942 2781943

सेवा में

शाखा प्रबन्धक
केनरा बैंक राजपुर रोड शाखा
देहरादून।

पत्रांक रा0प0का0 / 2655 / लेखा–2(ध0अ0) / 2013–14 दिनांक :– 28 फरवरी, 2014.

महोदय

कृपया संलग्न चैक संख्या 460702 (केनरा बैंक राजपुर रोड शाखा देहरादून) दिनांक 26 फरवरी, 2014 धनराशि रु0 52,00,00,000.00 (बावन करोड मात्र) को निम्न विवरणानुसार जिला परियोजना अधिकारियों, सर्व शिक्षा अभियान के बैंक खातों में तत्काल इलैक्ट्रानिकली स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

क्र. सं.	नाम	बैंक का नाम व आई0एफ0सी0 कोड	खाता संख्या	धनराशि (₹ में)
1	जिला परियोजना अधिकारी अल्मोड़ा	पी.न.बी. अल्मोड़ा IFS-PUNB0962000	0962000100195351	62000000.00
2	जिला परियोजना अधिकारी बागेश्वर	पी.एन.बी.बागेश्वर IFS-PUNB0481600	4816000100002798	25000000.00
3	जिला परियोजना अधिकारी चमोली	पी.एन.बी.गोपेश्वर IFS-PUNB0408300	4083000100026196	60000000.00
4	जिला परियोजना अधिकारी चम्पावत	पी.एन.बी.चम्पावत IFS-PUNB0495400	4954000400000019	30000000.00
5	जिला परियोजना अधिकारी देहरादून	पी.न.बी.देहरादून IFS-PUNB0442200	4422000101045306	33000000.00
6	जिला परियोजना अधिकारी हरिद्वार	केनरा बैंक हरिद्वार	2225101054334	50000000.00
7	जिला परियोजना अधिकारी नैनीताल	पी.एन.बी नैनीताल IFS-PUNB0187100	1871000100554406	25000000.00
8	जिला परियोजना अधिकारी पौड़ी	केनरा बैंक पौड़ी	3211101000096	35000000.00
9	जिला परियोजना अधिकारी पिथौरागढ	पी.एन.बी पिथौरागढ IFS-PUNB0167200	1672000100112337	20000000.00
10	जिला परियोजना अधिकारी रुद्रप्रयाग	एस.बी.आई.रुद्रप्रयाग IFS-SBIN0002463	11255588045	40000000.00
11	जिला परियोजना अधिकारी टिहरी	केनरा बैंक टिहरी	2166101012223	45000000.00
12	जिला परियोजना अधिकारी उधमसिहंनगर	केनरा बैंक रुद्रपुर	2543101004778	70000000.00
13	जिला परियोजना अधिकारी उत्तरकाशी	पी.एन.बी उत्तरकाशी IFS-PUNB0088100	0881000100154136	25000000.00
			TOTAL	**520000000.00**

(बावन करोड़ मात्र)

भवदीया

(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक

पृष्ठांकन सं. :– रा0प0का0 / 2655 / लेखा–ध0अ0 / 2013–14 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :– सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का लेखों में लेखांकन सुनिश्चित करते हुए, उक्त धनराशि का व्यय वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में पारित आवर्ती तथा अनावर्ती मदों में करना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उक्त स्वीकृत धनराशि में अल्पकालिक अनुदेशकों हेतु बजट स्वीकृत नही है।

(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक

"उत्तराखण्ड सभी के लि शिक्षा परिषद"
राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग रायपुर देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2781941 2781942 2781943

सेवा में

शाखा प्रबन्धक
केनरा बैंक राजपुर रोड शाखा
देहरादून।

पत्रांक रा0प0का0/2913 /लेखा–2(ध0अ0)/2013–14 दिनांक :–31 मार्च, 2014.

महोदय

कृपया संलग्न चैक संख्या 460731(केनरा बैंक राजपुर रोड शाखा देहरादून) दिनांक 31 मार्च, 2014 धनराशि रु0 8,00,00,000.00 (आठ करोड मात्र) को निम्न विवरणानुसार जिला परियोजना अधिकारियों, सर्व शिक्षा अभियान के बैंक खातों में तत्काल इलैक्ट्रानिकली स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

क्र. सं.	नाम	बैंक का नाम व आई0एफ0सी0 कोड	खाता संख्या	धनराशि (रू में)
1	जिला परियोजना अधिकारी अल्मोड़ा	पी.न.बी. अल्मोड़ा IFS-PUNB0962000	0962000100195351	15000000.00
2	जिला परियोजना अधिकारी चमोली	पी.एन.बी.गोपेश्वर IFS-PUNB0408300	4083000100026196	10000000.00
3	जिला परियोजना अधिकारी देहरादून	पी.न.बी.देहरादून IFS-PUNB0442200	4422000101045306	20000000.00
4	जिला परियोजना अधिकारी टिहरी	केनरा बैंक टिहरी	2166101012223	12500000.00
5	जिला परियोजना अधिकारी उधमसिहंनगर	केनरा बैंक रुद्रपुर	2543101004778	12500000.00
6	जिला परियोजना अधिकारी उत्तरकाशी	पी.एन.बी उत्तरकाशी IFS-PUNB0088100	0881000100154136	10000000.00
			TOTAL	**80000000.00**

(आठ करोड़ मात्र)

भवदीया

(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक

पृष्ठांकन सं. :– रा0प0का0/2913 /लेखा–ध0अ0/2013–14 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :– सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का लेखों में लेखांकन सुनिश्चित करते हुए, उक्त धनराशि का व्यय वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में पारित आवर्ती तथा अनावर्ती मदों में करना सुनिश्चित करें।

(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक

"उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद"
राज्य परियोजना कार्यालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, रायपुर देहरादून
E-mail : spd-ssa-uk@nic.in
Website : htpp//:ssa.uk.gov.in
दूरभाष : 0135 – 2781941, 2781942, 2781943

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
केनरा बैंक, राजपुर रोड शाखा
देहरादून।

पत्रांक रा0प0का0/ 1311 /लेखा–2(ध0अ0)/2012–13 दिनांक 09 अगस्त, 2012.

महोदय,

कृपया संलग्न चैक संख्या 186763 (केनरा बैंक, राजपुर रोड शाखा, देहरादून) दिनांक 08 अगस्त 2012 धनराशि रु0 42,00,00,000.00 (बयालीस करोड मात्र) को निम्न विवरणानुसार जिला परियोजना अधिकारियों के बैंक खातों में तत्काल इलैक्ट्रानिकली स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

क्र. सं.	नाम	बैंक का नाम व आइ0 एफ0एस0 कोड	खाता संख्या	धनराशि (रू0में)
1	जिला परियोजना अधिकारी अल्मोड़ा	केनरा बैंक अल्मोड़ा	2324101006602	4,00,00,000–00
2	जिला परियोजना अधिकारी बागेश्वर	पी.एन.बी.बागेश्वर IFS-PUNB0481600	4816000100002798	2,00,00,000–00
3	जिला परियोजना अधिकारी चमोली	पी.एन.बी.गोपेश्वर IFS-PUNB0408300	4083000100026196	3,50,00,000–00
4	जिला परियोजना अधिकारी चम्पावत	पी.एन.बी.चम्पावत IFS-PUNB0495400	4954000400000019	2,00,00,000–00
5	जिला परियोजना अधिकारी देहरादून	केनरा बैंक देहरादून	1182101018480	5,00,00,000–00
6	जिला परियोजना अधिकारी हरिद्वार	केनरा बैंक हरिद्वार	2225101054334	4,00,00,000–00
7	जिला परियोजना अधिकारी नैनीताल	पी.एन.बी नैनीताल IFS-PUNB0187100	1871000100554406	3,00,00,000–00
8	जिला परियोजना अधिकारी पौड़ी	केनरा बैंक पौड़ी	3211101000096	3,50,00,000–00
9	जिला परियोजना अधिकारी पिथौरागढ	पी.एन.बी पिथौरागढ IFS-PUNB0167200	1672000100112337	3,00,00,000–00
10	जिला परियोजना अधिकारी रुद्रप्रयाग	एस.बी.आई.रुद्रप्रयाग IFS-SBIN0002463	11255588045	2,50,00,000–00
11	जिला परियोजना अधिकारी टिहरी	केनरा बैंक टिहरी	2166101012223	4,00,00,000–00
12	जिला परियोजना अधिकारी उधमसिंह न0	केनरा बैंक रुद्रपुर	2543101004778	3,00,00,000–00
13	जिला परियोजना अधिकारी उत्तरकाशी	पी.एन.बी उत्तरकाशी IFS-PUNB0088100	0881000100154136	2,50,00,000–00
		योग		42,00,00,000–00

(बयालीस करोड़ मात्र)

भवदीया,

(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक
राज्य परियोजना कार्यालय

पृष्ठांकन सं.– रा0प0का0/ 1311 /लेखा–ध0अ0/2012–13/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि– सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का लेखों में लेखांकन सुनिश्चित करते हुए मासिक कार्ययोजना एवं बजट के अनुसार अधिकतम व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक

"उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद"
राज्य परियोजना कार्यालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, रायपुर देहरादून
E-mail : spd-ssa-uk@nic.in
Website : htpp//:ssa.uk.gov.in
दूरभाष : 0135 – 2781941, 2781942, 2781943

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
पंजाब नेशनल बैंक, विधान सभा मार्ग शाखा
देहरादून।

पत्रांक रा0प0का0/ 919 /लेखा–2(ध0अ0)/2012–13 दिनांक: 29 जून, 2011.

महोदय,

कृपया संलग्न चैक संख्या 914696 (पंजाब नेशनल बैंक, विधान सभा मार्ग शाखा) दिनांक 28 जून 2012 धनराशि रु0 20,00,00,000.00 (बीस करोड मात्र) को निम्न विवरणानुसार जिला परियोजना अधिकारियों के बैंक खातों में तत्काल इलैक्ट्रानिकली स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

क. सं.	नाम	बैंक का नाम व आइ0 एफ0एस0 कोड	खाता संख्या	धनराशि (रू0में)
1	जिला परियोजना अधिकारी अल्मोड़ा	पी.एन.बी. अल्मोड़ा	0962000100195351	2,00,00,000–00
2	जिला परियोजना अधिकारी बागेश्वर	पी.एन.बी.बागेश्वर	4816000100002798	1,00,00,000–00
3	जिला परियोजना अधिकारी चमोली	पी.एन.बी.गोपेश्वर	4083000100026196	2,00,00,000–00
4	जिला परियोजना अधिकारी चम्पावत	पी.एन.बी.चम्पावत	4954000400000019	1,00,00,000–00
5	जिला परियोजना अधिकारी देहरादून	पी.एन.बी.देहरादून	4422000101045306	3,00,00,000–00
6	जिला परियोजना अधिकारी हरिद्वार	पी.एन.बी हरिद्वार	3924000100131941	1,00,00,000–00
7	जिला परियोजना अधिकारी नैनीताल	पी.एन.बी नैनीताल	1871000100554406	1,00,00,000–00
8	जिला परियोजना अधिकारी पौड़ी	पी.एन.बी पौड़ी	1370000100112819	2,00,00,000–00
9	जिला परियोजना अधिकारी पिथौरागढ	पी.एन.बी पिथौरागढ	1672000100112337	3,00,00,000–00
10	जिला परियोजना अधिकारी रुद्रप्रयाग	एस.बी.आई.रुद्रप्रयाग IFS-SBIN0002463	11255588045	1,00,00,000–00
11	जिला परियोजना अधिकारी टिहरी	पी.एन.बी टिहरी	3302000105019877	1,00,00,000–00
12	जिला परियोजना अधिकारी उधमसिंह न0	पी.एन.बी रुद्रपुर	0833000101151726	1,00,00,000–00
13	जिला परियोजना अधिकारी उत्तरकाशी	पी.एन.बी उत्तरकाशी	0881000100154136	1,00,00,000–00
		योग		20,00,00,000–00

(बीस करोड़ मात्र)

भवदीया,

(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक
राज्य परियोजना कार्यालय

पृष्ठांकन सं.– रा0प0का0/ 919 /लेखा–ध0अ0/2012–13/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि– सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का लेखों में लेखांकन सुनिश्चित करते हुए मासिक कार्ययोजना एवं बजट के अनुसार अधिकतम व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक
राज्य परियोजना कार्यालय

"उत्तराखण्ड सभी के लि शिक्षा परिषद"
राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग रायपुर देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2781941 2781942 2781943

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

सेवा में

शाखा प्रबन्धक
केनरा बैंक राजपुर रोड शाखा
देहरादून।

पत्रांक रा0प0का0/1227/लेखा–2(ध0अ0)/2016–17 दिनांक :– 8 नवम्बर, 2016.

महोदय

कृपया संलग्न चैक संख्या 537483 (केनरा बैंक राजपुर रोड शाखा देहरादून) दिनांक 08.11.2016 धनराशि रु0 2,29,29,000.00 (दो करोड उडन्तीस लाख उडन्तीस हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार जिला परियोजना अधिकारियों, सर्व शिक्षा अभियान के बैंक खातों में तत्काल इलैक्ट्रानिकली स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

क्र. सं.	नाम	बैंक का नाम व आई0एफ0सी0 कोड	खाता संख्या	धनराशि
1	जिला परियोजना अधिकारी अल्मोड़ा	पी.न.बी. अल्मोड़ा	0962000100195351	2154000.00
2	जिला परियोजना अधिकारी बागेश्वर	पी.एन.बी.बागेश्वर IFS-PUNB0481600	4816000100002798	602000.00
3	जिला परियोजना अधिकारी चमोली	पी.एन.बी.गोपेश्वर IFS-PUNB0408300	4083000100026196	1064000.00
4	जिला परियोजना अधिकारी चम्पावत	पी.एन.बी.चम्पावत IFS-PUNB0495400	4954000400000019	925000.00
5	जिला परियोजना अधिकारी देहरादून	**AXIS bank IFSC UTIB0002675**	915010044575036	4020000.00
6	जिला परियोजना अधिकारी हरिद्वार	**पी.एन.बी हरिद्वार** IFS-PUNB0392400	3924000100131941	3078000.00
7	जिला परियोजना अधिकारी नैनीताल	पी.एन.बी नैनीताल IFS-PUNB0187100	1871000100554406	1364000.00
8	जिला परियोजना अधिकारी पौड़ी	केनरा बैंक पौड़ी	3211101000096	1638000.00
9	जिला परियोजना अधिकारी पिथौरागढ	पी.एन.बी पिथौरागढ IFS-PUNB0167200	1672000100112337	2672000.00
10	जिला परियोजना अधिकारी रुद्रप्रयाग	**पी.एन.बी रूद्रप्रयाग** IFS-PUNB0665900	6659000100047118	466000.00
11	जिला परियोजना अधिकारी टिहरी	केनरा बैंक टिहरी	2166101012223	1543000.00
12	जिला परियोजना अधिकारी उधमसिहंनगर	केनरा बैंक रुद्रपुर	2543101004778	1768000.00
13	जिला परियोजना अधिकारी उत्तरकाशी	पी.एन.बी उत्तरकाशी IFS-PUNB0088100	0881000100154136	1635000.00
			TOTAL	**22929000.00**

भवदीय
Amita
(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक

पृष्ठांकन सं. :– रा0प0का0/ /लेखा–ध0अ0/2016–17 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :– सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का व्यय वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2016–17 में स्वीकृत अनावर्ती मद–निर्माण कार्य मे व्यय करना सुनिश्चित करें।

Amita
(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक

"उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद"
राज्य परियोजना कार्यालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, रायपुर देहरादून
E-mail : spd-ssa-uk@nic.in
Website : htpp//:ssa.uk.gov.in
दूरभाष : 0135 – 2781941, 2781942, 2781943

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
केनरा बैंक, राजपुर रोड शाखा
देहरादून।

पत्रांक रा0प0का0/ 559 /लेखा–2(ध0अ0)/2012–13 दिनांक 28 मई, 2012.

महोदय,

कृपया संलग्न चैक संख्या 183534 (केनरा बैंक, राजपुर रोड शाखा, देहरादून) दिनांक 28 मई 2012 धनराशि ₹ 390000000.00 (उन्चालीस करोड मात्र) को निम्न विवरणानुसार जिला परियोजना अधिकारियों के बैंक खातों में तत्काल इलैक्ट्रानिकली स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

क्र. सं.	नाम	बैंक का नाम व आइ0 एफ0एस0 कोड	खाता संख्या	धनराशि (रू0में)
1	जिला परियोजना अधिकारी अल्मोड़ा	केनरा बैंक अल्मोड़ा	2324101006602	15000000-00
2	जिला परियोजना अधिकारी बागेश्वर	पी.एन.बी.बागेश्वर IFS-PUNB0481600	4816000100002798	20000000-00
3	जिला परियोजना अधिकारी चमोली	पी.एन.बी.गोपेश्वर IFS-PUNB0408300	4083000100026196	50000000-00
4	जिला परियोजना अधिकारी चम्पावत	पी.एन.बी.चम्पावत IFS-PUNB0495400	4954000400000019	20000000-00
5	जिला परियोजना अधिकारी देहरादून	केनरा बैंक देहरादून	1182101018480	40000000-00
6	जिला परियोजना अधिकारी नैनीताल	पी.एन.बी नैनीताल IFS-PUNB0187100	1871000100554406	40000000-00
7	जिला परियोजना अधिकारी पिथौरागढ	पी.एन.बी पिथौरागढ IFS-PUNB0167200	1672000100112337	65000000-00
8	जिला परियोजना अधिकारी रुद्रप्रयाग	एस.बी.आई.रुद्रप्रयाग IFS-SBIN0002463	11255588045	35000000-00
9	जिला परियोजना अधिकारी टिहरी	केनरा बैंक टिहरी	2166101012223	60000000-00
10	जिला परियोजना अधिकारी उत्तरकाशी	पी.एन.बी उत्तरकाशी IFS-PUNB0088100	0881000100154136	45000000-00
		योग		390000000-00

(उन्तालीस करोड़ मात्र)

भवदीय

वित्त अधिकारी
राज्य परियोजना कार्यालय

पृष्ठांकन सं.– रा0प0का0/ 559 /लेखा–ध0अ0/2012–13/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि– सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का लेखों में लेखांकन सुनिश्चित करते हुए मासिक कार्ययोजना एवं बजट के अनुसार अधिकतम व्यय करना सुनिश्चित करें।

वित्त अधिकारी
राज्य परियोजना कार्यालय

No. F. 10-4/2013-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy

ADDENDUM

Shastri Bhawan, New Delhi
12th July, 2013

Subject: Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) – 193rd Meeting of the Project Approval Board (PAB) held on 25.02.2013 – Circulation of Addendum to the Minutes – SSA, Uttarakhand

Minutes of the 193rd PAB meeting were issued vide this Ministry's letter of even number dated 13th May, 2013. Uttarakhand has raised an additional demand due to natural calamity of floods/heavy rains in Uttarakhand because of which, school infrastructure was either completely or partially damaged. In order to provide additional outlay in 2013-14 to cover the construction of new schools and providing major repairs to the partially damaged schools, the following addendum to the Minutes of the 193rd meeting of the PAB held on 25th February 2013 in respect of SSA, Uttarakhand is approved.

Para 7.1

(a) **New schools/ School buildings/ Civil Works Construction (Rs. 2395.01 lakh)**

42 primary school buildings and 15 upper primary school buildings in 9 districts have been completely damaged due to the floods/heavy rains. In addition 302 primary schools and 73 upper primary schools were partly damaged.

As habitations have either been relocated or have become unserved, they have to be provided a neighbourhood school as per the RTE norms.

An additional outlay of Rs. 1253.26 lakh is approved for new school buildings (Rs. 753.26 lakh) and major repairs to schools (Rs. 500 lakh) as detailed below: -

S.No.	Activity	Phy.	Fin.
1.	New Schools (Primary)	42	472.91
2.	New Schools (Upper Primary)	15	280.35
3.	Major Repairs to Schools (Primary and Upper Primary)		500.00
	Total	**57**	**1253.26**

Major repairs are sanctioned as a special case on the condition that the State will follow all the conditions given in the SSA Framework of implementation for this component.

TLE @ Rs. 2,000/- per primary school and @ Rs. 50,000/- per upper primary school will be a deferred liability till the completion of the school buildings.

As a result of the above, additional outlay approved the total civil works outlay for 2013-14 is Rs. 2395.01 lakh.

This works out to 6.32% of the total State outlay.

Para 7.3.7 Innovation (Rs. 51.13 lakh)

The State has requested for councelling for about 2000 children suffering from post Traumatic Stress disorder in the worst affected 4 districts. An outlay of Rs. 10 lakh in 4 districts of Rudraprayag, Uttarkashi, Chamoli, and Pithoragarh is approved under innovative activities to provide counseling support.

The overall outlay under under innovation after factoring in the above additional Rs. 10 lakh is Rs. 51.13 lakh.

Para 8 The revised outlay approved for SSA, Uttarakhand for 2013-14 is as under:

(Rs. in lakh)

Sr. No	Programme	Spill Over Outlay	Fresh Outlay	Total Outlay
1.	SSA	1153.75	36522.71	37676.46
2.	KGBV	0.00	411.46	411.46
	Total	1153.75	36934.17	38087.91

Para 9. 13th Finance Commission award

Outlay approved	Capital Head (all civil works under SSA & KGBV)	General Head	13th FC Award	Net General Head	GOI Share 65%		
					Capital Head	General Head	Total
38087.91	2395.01	35692.91	4500.00	31192.91	1556.75	20275.39	21832.14

The State Summary is at **Annexure-I** and the district costing sheets are at **Annexure-II.**

Other items remain unaltered.

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Govt. India

Distribution as per normal list.

"उत्तराखण्ड सभी के लि शिक्षा परिषद"
राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग रायपुर देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2781941 2781942 2781943

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

सेवा में

शाखा प्रबन्धक
केनरा बैंक राजपुर रोड शाखा
देहरादून।

पत्रांक रा0प्र0का0 / 1770 /लेखा–2(ध0अ0) / 2015–16 दिनांक :– 19 नवम्बर, 2015.

महोदय

कृपया संलग्न चैक संख्या 132346 (केनरा बैंक राजपुर रोड शाखा देहरादून) दिनांक 18.11.2015 धनराशि रु0 31,63,31,000.00(रू0ईकतीस करोड त्रैसठ लाख ईकतीस हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार जिला परियोजना अधिकारियों, सर्व शिक्षा अभियान के बैंक खातों में तत्काल इलैक्ट्रानिकली स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

क्र. सं.	नाम	बैंक का नाम व आई0एफ0सी0 कोड	खाता संख्या	धनराशि (रू में)
1	जिला परियोजना अधिकारी अल्मोड़ा	canara bank.almora	2324101006602	**25677000.00**
2	जिला परियोजना अधिकारी बागेश्वर	पी.एन.बी.बागेश्वर IFS-PUNB0481600	4816000100002798	**11507000.00**
3	जिला परियोजना अधिकारी चमोली	पी.एन.बी.गोपेश्वर IFS-PUNB0408300	4083000100026196	**23186000.00**
4	जिला परियोजना अधिकारी चम्पावत	पी.एन.बी.चम्पावत IFS-PUNB0495400	4954000400000019	**12614000.00**
5	जिला परियोजना अधिकारी देहरादून	canara bank, dehradun	1182101018480	**37570000.00**
6	जिला परियोजना अधिकारी हरिद्वार	canara bank, haridwar	2225101053042	**47733000.00**
7	जिला परियोजना अधिकारी नैनीताल	पी.एन.बी नैनीताल IFS-PUNB0187100	1871000100554406	**16159000.00**
8	जिला परियोजना अधिकारी पौड़ी	canara bank, pauri	3211101000096	**20718000.00**
9	जिला परियोजना अधिकारी पिथौरागढ	पी.एन.बी पिथौरागढ IFS-PUNB0167200	1672000100112337	**32737000.00**
10	जिला परियोजना अधिकारी रुद्रप्रयाग	एस.बी.आई.रुद्रप्रयाग IFS-SBIN0002463	11255588045	**9596000.00**
11	जिला परियोजना अधिकारी टिहरी	canara bank., tehri	2166101012223	**21679000.00**
12	जिला परियोजना अधिकारी उधमसिहंनगर	canara bank., rudrapur	2543101004778	**41364000.00**
13	जिला परियोजना अधिकारी उत्तरकाशी	पी.एन.बी उत्तरकाशी IFS-PUNB0088100	0881000100154136	**15791000.00**
			TOTAL	**316331000.00**

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक

पृष्ठांकन सं. :– रा0प0का0 / 1770 /लेखा–ध0अ0 / 2015–16 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :– सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का लेखों में लेखांकन सुनिश्चित करते हुए, उक्त धनराशि का व्यय वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में पारित आवर्ती तथा अनावर्ती मदों में ही व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक

No. F. 10-5/2013-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy

New Delhi, the 6th May,2013.

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan
New Delhi

Subject:- Release of 1st tranche of 1st installment of Central share under SSA for the year 2013-14(Plan) to SSA, Uttarakhand.

F.C.

Sir,

The Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 193rd Meeting held on 25th February,2013 approved the Annual Work Plan ad Budget 2013-14 for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

06/06/13

2. I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs.20,79,000/- (Rupees twenty lakh seventy nine thousand only)** under **Grants-in-aid For creation of Capital Assets Head as** 1st tranche of 1st installment of Central share for implementation of SSA, NPEGEL, KGBV within the ceiling of PAB approved outlay for 2013-14 to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun. With this release, the total releases will be Rs.9513.30 lakh for the year 2013-14.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The money sanctioned herein should be spent on priority to provide norms and standards as laid down in the schedule to RTE Act, 2009.

5. The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

6. The State will maintain separate accounts for grants released under Grant-in-aid General and Grants for creation of Capital Assets. Further at the end of the financial year State will provide expenditure and unspent balance on General and Capital object head separately.

(MANJEET KUMAR)
Dy. School Education & Literacy
Govt. of India
New Delhi

7. The amount sanctioned will be drawn by the Drawing and Disbursing Officer (Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Government of India New Delhi on a grant-in-aid bill and disbursed to the grantee through electronic/telegraphic transfer of fund to the State Project Director, Uttarkhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand during the current financial year 2013-14. The details of bank account of the society is as follow:

Account No. 1182101012885
Canara Bank, Anekant Palace
Rajpur Road, Dehrudun

8. Authorisation letter received from the payee is enclosed for making the e-payment in favour of Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

9. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2014 and shall be utilized within a reasonable period from the date of drawl.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities proposed in the Work Plan for the year 2013-14 and as approved by the Project Approval Board, and by the Government of India on the basis norms of expenditure.

(iii) The assets, if any, acquired wholly or substantially out of this grant, should not, without the prior sanction of the Government of India, be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant has been sanctioned.

(iv) The grantee shall maintain a separate and proper account of the expenditure incurred out of the grant and the accounts so maintained shall be open to audit by the Comptroller & Auditor General of India or any authority deputed by him for the purpose as per rules.

(v) The State Implementation Society shall keep the amounts sanctioned for SSA/NPEGEL under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(vi) The State Government shall release their correspondence share (35%) against AWP&B 2013-14 to Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand in time as per stipulation mentioned in the Framework of the scheme besides releasing the entire accumulated deficit of State share since 2000-2001. Subsequent installment of grant would be sanctioned only after the entire backlog of State share including the one due against the current year approved budget is released by the State Government to the State Society.

(vii) Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(viii) The amount sanctioned for a district shall be made available to the district level institution authorized for the implementation of SSA. Individual districts shall spend the amount given to them on the items proposed by them in the District Plans for the year 2012-13 and as approved by the PAB, and in accordance with other general principles and Framework of the scheme and the terms of this sanction.

Kumar

(...JEET KUMAR)
...Under Secretary
...Min. of H.R.D.
D/o School Education & Literacy
...Govt. of India
...New Delhi

(ix) The grant shall be utilized only for undertaking activities as approved by the Government of India on the basis of norms of expenditure.

(x) State Mission Authority of Education for All, Uttarakhand shall fully implement the Official Language Policy of the Union Government i.e. It shall full comply with Official Language Act, 1963 and Office Language (used for the official purpose of the Union) Rules, 1976 etc.

(xi) The grantee shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year. An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved project duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year. The unspent balance, if any shall be taken into account before funds or subsequent years are released.

(xii) A register of assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be acquired should be sent to this Ministry not later than one month from the close of the financial year. Such copies should continue to be furnished even after Government grant ceased. The Statements shall relate to all assets created wholly or substantially out of the Governmental grant upto the end of the period to which the return relates.

(xiii) The accounts and other records of the Project Officers and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(xiv) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme and reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(xv) There shall be no appointment of permanent staff, except additional teachers only as per SSA norms. The existing staff of the State Government should be optimally utilized. The principal work of project implementation shall be on the mainstream administrative establishment at State and district levels. However, in case there is any need to appoint contractual staff for a limited period for the performance of specialised jobs for which expertise is not available with them. Such contractual staff may only be hired by the district/block/village levels only and the cost maintained within 6% management cost as envisaged under the scheme.

(xvi) The guidelines issued by the Government of India from time to time regarding monitoring management and financial control and other procedure would be followed in the execution of the Project.

(xvii) The State Government should give a written commitment for meeting its share of the SSA/NPEGEL outlay.

(xviii) First installment of the State share should also be released to the Society within one month of the release of central share to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

(xix) Teachers appointed against posts created through SSA funds should be made accountable to the VEC for at least salary payment. The latter would monitor the attendance before releasing the salary.

(xx) VECs or equivalent bodies should be constituted and accounts opened to incur expenditure under teachers grant, civil works, maintenance grants, school grants and other such expenditure which has to be incurred only through these bodies as per SSA norms and should be utilized within one month of its release.

(xxi) State Government will maintain their level of investment in elementary education as in 1999-2000 and give the details of this to Government of India before the release of installment. The contribution as State share for SSA will be over and above this investment.

(xxii) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if any, has been transferred to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure as far as money already released is concerned.

(xxiii) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render toe grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xxiv) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xxv) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

10. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 Department of School Education and Literacy; Major Head 2202; General Education –01-Elementary Education -796-Scheduled Tribe sub plans - 03- Sarva Shiksha Abhiyan - 03.02 General Component (PSK) - 03.02.35 Grant-in-aid for creation of capital assets 2013-14(Plan).

11. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 2472/2013/IFD dated 26.04.2013 and IF-II vide their Dy. No.757/2013/IF-II dated 30.04.2013.

12. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

13. No U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23073542

(MANJEET KUMAR)
Under Secretary
Min. of H.R.D.
(शिक्षा विभाग)
Dt. School Education & Literacy
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Copy forwarded to:

1. State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand The grantee institution is required to submit the under mentioned documents as per terms and conditions of the sanction letter to enable the Ministry to release the grant:-

   (a) Bond for **Rs. 9513.30 lakh** in revised format.
   (b) Authorisation letter as in the revised format.

2. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand , Dehradun.

3. The Principal Secretary (Education), Government of Uttarakhand, Sachicalaya, Dehradun-248001, Uttarakahnd. The State Government is requested to kindly furnish written commitment as per para 6 (vi) of the sanction.

4. The Drawing and disbursing Officer (Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy in duplicate for drawal and disbursement electronically.

5. Office of the Director General of Audit-I Central Revenue OAD-II Section, AGCR Building I.P. Estate, New Delhi 110002.

6. The Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.

7. The Accountant General, Uttarakhand, Dehradun

8. IF-2 Section/E.C. Unit/IFD/EE-15 section.

9. Shri Shailander Sharma, Chief Consultant TSG Ed-CIL New Delhi.

10. Guard File.

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

7. The amount sanctioned will be drawn by the Drawing and Disbursing Officer(Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Government of India New Delhi on a grant-in-aid bill and disbursed to the grantee through electronic/telegraphic transfer of fund to the State Project Director, Uttarkhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand during the current financial year 2013-14. The details of bank account of the society is as follow:

Account No. 1182101012885
Canara Bank, Anekant Palace
Rajpur Road, Dehrudun

8. Authorisation letter received from the payee is enclosed for making the e-payment in favour of Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

9. The grant shall be subject to the following conditions:

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2014 and shall be utilized within a reasonable period from the date of drawl.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities proposed in the Work Plan for the year 2013-14 and as approved by the Project Approval Board, and by the Government of India on the basis norms of expenditure.

(iii) The assets, if any, acquired wholly or substantially out of this grant, should not, without the prior sanction of the Government of India, be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant has been sanctioned.

(iv) The grantee shall maintain a separate and proper account of the expenditure incurred out of the grant and the accounts so maintained shall be open to audit by the Comptroller & Auditor General of India or any authority deputed by him for the purpose as per rules.

(v) The State Implementation Society shall keep the amounts sanctioned for SSA/NPEGEL under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(vi) The State Government shall release their correspondence share (35%) against AWP&B 2013-14 to Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand in time as per stipulation mentioned in the Framework of the scheme besides releasing the entire accumulated deficit of State share since 2000-2001. Subsequent installment of grant would be sanctioned only after the entire backlog of State share including the one due against the current year approved budget is released by the State Government to the State Society.

(vii) Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(viii) The amount sanctioned for a district shall be made available to the district level institution authorized for the implementation of SSA. Individual districts shall spend the amount given to them on the items proposed by them in the District Plans for the year 2013-14 and as approved by the PAB, and in accordance with other general principles and Framework of the scheme and the terms of this sanction.

No. F. 10-5/2013-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy

New Delhi, the 6th May,2013.

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan
New Delhi

Subject:- Release of 1st tranche of 1st installment of Central share under SSA for the year 2013-14(Plan) to SSA, Uttarakhand.

Sir,

The Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 193rd Meeting held on 25th February,2013 approved the Annual Work Plan ad Budget 2013-14 for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

2. I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs.4,77,59,000/- (Rupees four crore seventy seven lakh fifty nine thousand only)** under **Grants-in-aid For creation of Capital Assets Head** as 1st tranche of 1st installment of Central share for implementation of SSA, NPEGEL, KGBV within the ceiling of PAB approved outlay for 2013-14 to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun. With this release, the total releases will be Rs.9513.30 lakh for the year 2013-14.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

5. The money sanctioned herein should be spent on priority to provide norms and standards as laid down in the schedule to RTE Act, 2009.

6. The State will maintain separate accounts for grants released under Grant-in-aid General and Grants for creation of Capital Assets. Further at the end of the financial year State will provide expenditure and unspent balance on General and Capital object head separately.

(MANJEET KUMAR)

-2-

The amount sanctioned will be drawn by the Drawing and Disbursing Officer(Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Government of India New Delhi on a grant-in-aid bill and disbursed to the grantee through electronic/telegraphic transfer of fund to the State Project Director, Uttarkhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand during the current financial year 2013-14. The details of bank account of the society is as follow:

Account No. 1182101012885
Canara Bank, Anekant Palace
Rajpur Road, Dehrudun

8. Authorisation letter received from the payee is enclosed for making the e-payment in favour of Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

9. The grant shall be subject to the following conditions:

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2014 and shall be utilized within a reasonable period from the date of drawl.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities proposed in the Work Plan for the year 2013-14 and as approved by the Project Approval Board, and by the Government of India on the basis norms of expenditure.

(iii) The assets, if any, acquired wholly or substantially out of this grant, should not, without the prior sanction of the Government of India, be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant has been sanctioned.

(iv) The grantee shall maintain a separate and proper account of the expenditure incurred out of the grant and the accounts so maintained shall be open to audit by the Comptroller & Auditor General of India or any authority deputed by him for the purpose as per rules.

(v) The State Implementation Society shall keep the amounts sanctioned for SSA/NPEGEL under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(vi) The State Government shall release their correspondence share (35%) against AWP&B 2013-14 to Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand in time as per stipulation mentioned in the Framework of the scheme besides releasing the entire accumulated deficit of State share since 2000-2001. Subsequent installment of grant would be sanctioned only after the entire backlog of State share including the one due against the current year approved budget is released by the State Government to the State Society.

(vii) Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(viii) The amount sanctioned for a district shall be made available to the district level institution authorized for the implementation of SSA. Individual districts shall spend the amount given to them on the items proposed by them in the District Plans for the year 2013-14 and as approved by the PAB, and in accordance with other general principles and Framework of the scheme and the terms of this sanction.

(ix) The grant shall be utilized only for undertaking activities as approved by the Government of India on the basis of norms of expenditure.

(x) State Mission Authority of Education for All, Uttarakhand shall fully implement the Official Language Policy of the Union Government i.e. It shall full comply with Official Language Act, 1963 and Office Language (used for the official purpose of the Union) Rules, 1976 etc.

(xi) The grantee shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year. An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved project duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year. The unspent balance, if any shall be taken into account before funds or subsequent years are released.

(xii) A register of assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be acquired should be sent to this Ministry not later than one month from the close of the financial year. Such copies should continue to be furnished even after Government grant ceased. The Statements shall relate to all assets created wholly or substantially out of the Governmental grant upto the end of the period to which the return relates.

(xiii) The accounts and other records of the Project Officers and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(xiv) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme and reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(xv) There shall be no appointment of permanent staff, except additional teachers only as per SSA norms. The existing staff of the State Government should be optimally utilized. The principal work of project implementation shall be on the mainstream administrative establishment at State and district levels. However, in case there is any need to appoint contractual staff for a limited period for the performance of specialised jobs for which expertise is not available with them. Such contractual staff may only be hired by the district/block/village levels only and the cost maintained within 6% management cost as envisaged under the scheme.

(xvi) The guidelines issued by the Government of India from time to time regarding monitoring management and financial control and other procedure would be followed in the execution of the Project.

(xvii) The State Government should give a written commitment for meeting its share of the SSA/NPEGEL outlay.

(xviii) First installment of the State share should also be released to the Society within one month of the release of central share to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

(xix) Teachers appointed against posts created through SSA funds should be made accountable to the VEC for at least salary payment. The latter would monitor the attendance before releasing the salary.

(xx) VECs or equivalent bodies should be constituted and accounts opened to incur expenditure under teachers grant, civil works, maintenance grants, school grants and other such expenditure which has to be incurred only through these bodies as per SSA norms and should be utilized within one month of its release.

(xxi) State Government will maintain their level of investment in elementary education as in 1999-2000 and give the details of this to Government of India before the release of installment. The contribution as State share for SSA will be over and above this investment.

(xxii) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if any, has been transferred to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure as far as money already released is concerned.

(xxiii) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render toe grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xxiv) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xxv) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

10. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 Department of School Education and Literacy; Major Head 2202; General Education –01-Elementary Education -111- Sarva Shiksha Abhiyan - 01-General Component- 01.02 - Sarva Shiksha Abhiyan (PSK) - 01.02.35 Grant-in-aid for creation of capital assets 2013-14(Plan).

11. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 2472/2013/IFD dated 26.04.2013 and IF-II vide their Dy. No.757/2013/IF-II dated 30.04.2013.

12. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

13. No U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23073542

Copy forwarded to:

1. State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand The grantee institution is required to submit the under mentioned documents as per terms and conditions of the sanction letter to enable the Ministry to release the grant:-

   (a) Bond for **Rs. 9513.30 lakh** in revised format.
   (b) Authorisation letter as in the revised format.

2. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand , Dehradun.

3. The Principal Secretary (Education), Government of Uttarakhand, Sachicalaya, Dehradun-248001, Uttarakahnd. The State Government is requested to kindly furnish written commitment as per para 6 (vi) of the sanction.

4. The Drawing and disbursing Officer (Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy in duplicate for drawal and disbursement electronically.

5. Office of the Director General of Audit-I Central Revenue OAD-II Section, AGCR Building I.P. Estate, New Delhi 110002.

6. The Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.

7. The Accountant General, Uttarakhand, Dehradun

8. IF-2 Section/E.C. Unit/IFD/EE-15 section.

9. Shri Shailander Sharma, Chief Consultant TSG Ed-CIL New Delhi.

10. Guard File.

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23073542

No.F.10-2/2015-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
[Department of School Education and Literacy]

New Delhi, the 25th August, 2015

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan,
New Delhi

Subject:- Release of balance of 1st installment of Central share under SSA for the year 2015-16 to SSA, Uttarakhand.

Sir,

The Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 222nd Meeting held on 19th March, 2015 approved the Annual Work Plan and Budget 2015-16 for implementation of SSA & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

2. I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs. 4,38,16,000/- (Rupees four crore thirty eight lakh sixteen thousand only)** under **Capital Head for General Component** as balance of 1st installment of grants for implementation of SSA, & KGBV in Uttarakhand for the year 2015-16 to the SSA, Uttarakhand.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of implementation of the SSA and the Financial & Procurement Manual for SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The amount sanctioned will be released to the State Government of Uttarakhand, who will disburse the entire funds through electronic transfer to **Account No. 1182101012885, Canara Bank, Anekant Palace, Rajpur Road, Dehrudun,** Uttarkhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand immediately but not later than 15 days.

5. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2016.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities approved by the Project Approval Board of Department of School Education and Literacy, Govt. of India as per the Annual Work Plan for the year 2015-16.

(iii) The State Implementation Society (SIS) shall keep the amounts sanctioned for SSA/KGBV under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(iv) The State Govt shall release their corresponding share (35%) against the approved AWP&B 2015-16 to SSA, Uttarakhand in the bank account mentioned at para 4 above within one month of receipt of central share.

(v) SSA, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(vi) The grantee (SIS) shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year.

(vii) An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved programme duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-in-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year.

(viii) The accounts and other records of the SSA Project Officer and Implementation Institutions shall be opened to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(ix) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme.

(x) No permanent posts shall be created under the SSA funds. Teacher posts shall be created by the State Government even where such posts are supported by SSA funding. Project positions for SSA implementation would be temporary, upto the duration of the project only.

(xi) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if due has been transferred to the SSA, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure against central & state funds available with the SIS.

(xii) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xiii) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xiv) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

(xv) The unspent balance of Central assistance released to State during the previous years will be adjusted while releasing the balance amount of first installment due to the State.

6. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 - Department of School Education & Literacy, 3601 (Major Head) – Grants-in-aid to State Govt., 02 (Sub-Major Head) – Grants for State Plan Scheme, 186 (Minor Head) - Elementary Education -Sarva Shiksha Abhiyan, 01 (Sub Head) - General Component, 02 - Sarva Shiksha Abhiyan Component (Amount to be met from PSK), 35 – Grants for creation of Capital Assets, 2015-16 (Plan).

7. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, D-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115. On receipt of the sanction letter, the Principal Accounts Officer may issue an advice to the Reserve Bank of India (Central Accounts Sanction), Dehradun for affording credit to the balance of the State Government. The Principal Accounts Officer may forward a copy of the advice to the Accountant General and Finance Department of the State Government along with a copy to undersigned in the Department of School Education & Literacy. State Government shall send intimation regarding receipt of grant-in-aid to Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115.

8. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1108/2015/IFD dated 07.08.2015 and IF-II vide their Dy. No. 380/2015/IF-II dated 17.08.2015.

9. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

10. U.C. up to 2013-14 has been issued and hence no U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

No.F.10-2/2015-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
[Department of School Education and Literacy]

New Delhi, the 25th August, 2015

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan,
New Delhi

Subject:- Release of balance of 1st installment of Central share under SSA for the year 2015-16 to SSA, Uttarakhand.

Sir,

The Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 222nd Meeting held on 19th March, 2015 approved the Annual Work Plan and Budget 2015-16 for implementation of SSA & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

2. I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs.1,46,45,000/- (Rupees one crore forty six lakh forty five thousand only)** under **Capital Head for Schedule Caste Component** as balance 1st installment of grants for implementation of SSA, & KGBV in Uttarakhand during the year 2015-16 to the SSA, Uttarakhand..

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of implementation of the SSA and the Financial & Procurement Manual for SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The amount sanctioned will be released to the State Government of Uttarakhand, who will disburse the entire funds through electronic transfer to **Account No. 1182101012885, Canara Bank, Anekant Palace,Rajpur Road, Dehrudun,** Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand immediately but not later than 15 days.

5. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2016.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities approved by the Project Approval Board of Department of School Education and Literacy, Govt. of India as per the Annual Work Plan for the year 2015-16.

(iii) The State Implementation Society (SIS) shall keep the amounts sanctioned for SSA/KGBV under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(iv) The State Govt shall release their corresponding share (35%) against the approved AWP&B 2015-16 to SSA, Uttarakhand in the bank account maintained para 3 above with the month of receipt of central share.

(v) SSA, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(vi) The grantee (SIS) shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year.

(vii) An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved programme duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year.

(viii) The accounts and other records of the SSA Project Officer and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(ix) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme.

(x) No permanent posts shall be created under the SSA funds. Teacher posts shall be created by the State Government even where such posts are supported by SSA funding. Project positions for SSA implementation would be temporary, upto the duration of the project only.

(xiv) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if due has been transferred to the SSA, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure against central & state funds available with the SIS.

(xv) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xvi) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xvii) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

(xviii) The unspent balance of Central assistance released to State during the previous years will be adjusted while releasing the balance amount of first installment due to the State.

6. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 - Department of School Education & Literacy, 3601 (Major Head) – Grants-in-aid to State Govt., 02 (Sub-Major Head) – Grants for State Plan Scheme, 789(Minor Head) - Special Component Plan for Scheduled Castes, 04 (Sub Head) – Sarva Shiksha Abhiyan, 02 – General Component (Amount to be met from PSK), 35 – Grants for creation of Capital Assets, 2015-16 (Plan).

7. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, D-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115. On receipt of the sanction letter, the Principal Accounts Officer may issue an advice to the Reserve Bank of India (Central Accounts Sanction), Dehradun for affording credit to the balance of the State Government. The Principal Accounts Officer may forward a copy of the advice to the Accountant General and Finance Department of the State Government along with a copy to undersigned in the Department of School Education & Literacy. State Government shall send intimation regarding receipt of grant-in-aid to Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115.

8. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1108/2015/IFD dated 07.08.2015 and IF-II vide their Dy. No. 380/2015/IF-II dated 17.08.2015.

9. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

10. U.C. up to 2013-14 has been issued and hence no U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

No.F.10-2/2015-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
[Department of School Education and Literacy]

New Delhi, the 25th August, 2015

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan,
New Delhi

Subject:- Release of balance of 1st installment of Central share under SSA for the year 2015-16 to SSA, Uttarakhand.

Sir,

The Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 222nd Meeting held on 19th March, 2015 approved the Annual Work Plan and Budget 2015-16 for implementation of SSA & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

2. I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs. 18,58,000/- (Rupees eighteen lakh fifty eight thousand only)** under **Capital Head for Scheduled Tribe Component** as balance of 1st installment of grants for implementation of SSA, & KGBV in Uttarakhand during the year 2015-16 to the SSA, Uttarakhand.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of implementation of the SSA and the Financial & Procurement Manual for SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The amount sanctioned will be released to the State Government of Uttarakhand, who will disburse the entire funds through electronic transfer to **Account No. 1182101012885, Canara Bank, Anekant Palace, Rajpur Road, Dehrudun,** Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand immediately but not later than 15 days.

5. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2016.
(ii) It shall be utilized only for undertaking activities approved by the Project Approval Board of Department of School Education and Literacy, Govt. of India as per the Annual Work Plan for the year 2015-16.
(iii) The State Implementation Society (SIS) shall keep the amounts sanctioned for SSA/KGBV under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.
(iv) The State Govt shall release their corresponding share (35%) against the approved AWP&B 2015-16 to SSA, Uttarakhand in the bank account maintained para 3 above with the month of receipt of central share.
(v) SSA, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.
(vi) The grantee (SIS) shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year.
(vii) An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved programme duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year.

(viii) The accounts and other records of the SSA Project Officer and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(ix) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme.

(x) No permanent posts shall be created under the SSA funds. Teacher posts shall be created by the State Government even where such posts are supported by SSA funding. Project positions for SSA implementation would be temporary, upto the duration of the project only.

(xiv) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if due has been transferred to the SSA, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure against central & state funds available with the SIS.

(xv) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xvi) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xvii) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

(xviii) The unspent balance of Central assistance released to State during the previous years will be adjusted while releasing the balance amount of first installment due to the State.

6. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 - Department of School Education & Literacy, 3601 (Major Head) – Grants-in-aid to State Govt., 02 (Sub-Major Head) – Grants for State Plan Scheme, 796 (Minor Head) – Scheduled Tribes Sub Plan, 04 (Sub Head) – Sarva Shiksha Abhiyan, 02 – General Component (Amount to be met from PSK), 35 – Grants for creation of Capital Assets, 2015-16 (Plan).

7. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, D-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115. On receipt of the sanction letter, the Principal Accounts Officer may issue an advice to the Reserve Bank of India (Central Accounts Sanction), Dehradun for affording credit to the balance of the State Government. The Principal Accounts Officer may forward a copy of the advice to the Accountant General and Finance Department of the State Government along with a copy to undersigned in the Department of School Education & Literacy. State Government shall send intimation regarding receipt of grant-in-aid to Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115.

8. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1108/2015/IFD dated 07.08.2015 and IF-II vide their Dy. No. 380/2015/IF-II dated 17.08.2015.

9. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

10. U.C. up to 2013-14 has been issued and hence no U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

No.F.10-2/2015-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
[Department of School Education and Literacy]

New Delhi, the 25th August, 2015

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan,
New Delhi

Subject:- Release of balance of 1st installment of Central share under SSA for the year 2015-16 to SSA, Uttarakhand.

Sir,

The Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 222nd Meeting held on 19th March, 2015 approved the Annual Work Plan and Budget 2015-16 for implementation of SSA & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

2. I am directed to convey the sanction of the President to release of **Rs.46,06,86,000/-(Rupees forty six crore six lakh eighty six thousand only)** under **General Head for General Component** as balance of 1st installment of Central share for implementation of SSA & KGBV in Uttarakhand for the year 2015-16 to the SSA, Uttarakhand.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The amount sanctioned will be released to the State Government of Uttarakhand, who will disburse that entire funds through electronic transfer to **Account No. 1182101012885, Canara Bank, Anekant Palace, Rajpur Road, Dehradun, Uttarakhand** Sabhi Ke Liye Shikha Parishad, Dehradun, Uttarakhand immediately but not later than 15 days.

5. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2016.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities approved by the Project Approval Board of Department of School Education and Literacy, Govt. of India as per the Annual Work Plan for the year 2015-16.

(iii) The State Implementation Society (SIS) shall keep the amounts sanctioned for SSA/KGBV under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(iv) The State Government shall release their corresponding share (35%) against the approved AWP&B 2015-16 to SSA, Uttarakhand in the bank account mentioned at para 4 above within one month of receipt of central share.

(v) SSA, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(vi) The grantee (SIS) shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year.

(vii) An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved programme duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-in-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year.

(viii) The accounts and other records of the SSA Project Officer and Implementation Institutions shall be opened to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(ix) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme.

(x) No permanent posts shall be created under the SSA funds. Teacher posts shall be created by the State Government even where such posts are supported by SSA funding. Project positions for SSA implementation would be temporary, upto the duration of the project only.

(xi) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if due has been transferred to the SSA, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure against central & state funds available with the SIS.

(xii) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xiii) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xiv) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

(xv) The unspent balance of Central assistance released to State during the previous years will be adjusted while releasing the balance amount of first installment due to the State.

6. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 - Department of School Education and Literacy, 3601(Major Head)- Grants-in-aid to State Govt., 02 (Sub-Major Head)-Grants for State Plan Scheme, 186 (Minor Head)-Elementary Education – Sarva Shiksha Abhiyan, 01 (Sub Head)- General Component, 02 - Sarva Shiksha Abhiyan Component (Amount to be met from PSK), 31- Grants-in-aid General, 2015-16 (Plan).

7. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, D-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110115. On receipt of the sanction letter, the Principal Accounts Officer may issue an advice to the Reserve Bank of India (Central Accounts Sanction), Dehradun for affording credit to the balance of the State Government. The Principal Accounts Officer may forward a copy of the advice to the Accountant General and Finance Department of the State Government along with a copy to undersigned in the Department of School Education & Literacy. State Government shall send intimation regarding receipt of grant-in-aid to Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi-110115.

8. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1108/2015/IFD dated 07.08.2015 and IF-II vide their Dy. No. 380/2015/IF-II dated 17.08.2015.

9. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

10. U.C. up to 2013-14 has been issued and hence no U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

No.F.10-2/2015-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
[Department of School Education and Literacy]

New Delhi, the 25th August, 2015

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan,
New Delhi

Subject:- Release of balance of 1st installment installment of Central share under SSA for the year 2015-16 to SSA, Uttarakhand.

Sir,

The Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 222nd Meeting held on 19th March, 2015 approved the Annual Work Plan and Budget 2015-16 for implementation of SSA & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

2. I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs.15,39,85,000/- (Rupees fifteen crore thirty nine lakh eighty five thousand only)** under **General Head for Schedule Caste Component** as balance of 1st installment for implementation of SSA, & KGBV in Uttarakhand during the year 2015-16 to the SSA, Uttarakhand.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of implementation of the SSA and the Financial & Procurement Manual for SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The amount sanctioned will be released to the State Government of Uttarakhand, who will disburse the entire funds through electronic transfer to **Account No. 1182101012885, Canara Bank, Anekant Palace, Rajpur Road, Dehradun,** Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun, Uttarakhand immediately but not later than 15 days.

5. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2016.
(ii) It shall be utilized only for undertaking activities approved by the Project Approval Board of Department of School Education and Literacy, Govt. of India as per the Annual Work Plan for the year 2015-16.
(iii) The State Implementation Society (SIS) shall keep the amounts sanctioned for SSA/KGBV under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.
(iv) The State Government shall release their corresponding share (35%) against the approved AWP&B 2015-16 to SSA, Uttarakhand in the bank account maintained para 3 above with the month of receipt of central share.
(v) SSA, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.
(vi) The grantee (SIS) shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year.
(vii) An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved programme duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year.

(viii) The accounts and other records of the SSA Project Officer and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(ix) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme.

(x) No permanent posts shall be created under the SSA funds. Teacher posts shall be created by the State Government even where such posts are supported by SSA funding. Project positions for SSA implementation would be temporary, upto the duration of the project only.

(xiv) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if due has been transferred to the SSA, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure against central & state funds available with the SIS.

(xv) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xvi) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xvii) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

(xviii) The unspent balance of Central assistance released to State during the previous years will be adjusted while releasing the balance amount of first installment due to the State.

6. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 - Department of School Education & Literacy, 3601 (Major Head) – Grants-in-aid to State Govt., 02 (Sub-Major Head) – Grants for State Plan Scheme, 789(Minor Head) - Special Component Plan for Scheduled Castes, 04 (Sub Head) – Sarva Shiksha Abhiyan, 02 – General Component (Amount to be met from PSK), 31 - Grant-in-aid General, 2015-16 (Plan).

7. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, D-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115. On receipt of the sanction letter, the Principal Accounts Officer may issue an advice to the Reserve Bank of India (Central Accounts Sanction), Dehradun for affording credit to the balance of the State Government. The Principal Accounts Officer may forward a copy of the advice to the Accountant General and Finance Department of the State Government along with a copy to undersigned in the Department of School Education & Literacy. State Government shall send intimation regarding receipt of grant-in-aid to Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115.

8. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1108/2015/IFD dated 07.08.2015 and IF-II vide their Dy. No. 380/2015/IF-II dated 17.08.2015.

9. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

10. U.C. up to 2013-14 has been issued and hence no U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

No.F.10-2/2015-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
[Department of School Education and Literacy]

New Delhi, the 25th August, 2015

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan,
New Delhi

Subject:- Release of balance of 1st installment installment of Central share under SSA for the year 2015-16 to SSA, Uttarakhand.

Sir,

The Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 222nd Meeting held on 19th March, 2015 approved the Annual Work Plan and Budget 2015-16 for implementation of SSA & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

2. I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs. 1,95,33,000/- (Rupees one crore ninety five lakh thirty three thousand only)** under **General Head for Scheduled Tribe Component** as balance of 1st installment of grants for implementation of SSA, & KGBV in Uttarakhand for the year 2015-16 to the SSA, Uttarkhand.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of implementation of the SSA and the Financial & Procurement Manual for SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The amount sanctioned will be released to the State Government of Uttarakhand, who will disburse the entire funds through electronic transfer to **Account No. 1182101012885, Canara Bank, Anekant Palace, Rajpur Road, Dehradun,** Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun, Uttarakhand immediately but not later than 15 days.

5. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2016.
(ii) It shall be utilized only for undertaking activities approved by the Project Approval Board of Department of School Education and Literacy, Govt. of India as per the Annual Work Plan for the year 2015-16.
(iii) The State Implementation Society (SIS) shall keep the amounts sanctioned for SSA/KGBV under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.
(iv) The State Government shall release their corresponding share (35%) against the approved AWP&B 2015-16 to SSA, Uttarakhand in the bank account maintained para 3 above with the month of receipt of central share.
(v) SSA, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.
(vi) The grantee (SIS) shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year.
(vii) An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved programme duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year.

(viii) The accounts and other records of the SSA Project Officer and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(ix) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme.

(x) No permanent posts shall be created under the SSA funds. Teacher posts shall be created by the State Government even where such posts are supported by SSA funding. Project positions for SSA implementation would be temporary, upto the duration of the project only.

(xiv) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if due has been transferred to the SSA, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure against central & state funds available with the SIS.

(xv) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xvi) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xvii) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

(xviii) The unspent balance of Central assistance released to State during the previous years will be adjusted while releasing the balance amount of first installment due to the State.

6. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 - Department of School Education & Literacy, 3601 (Major Head) – Grants-in-aid to State Govt., 02 (Sub-Major Head) – Grants for State Plan Scheme, 796 (Minor Head) - Scheduled Tribes sub Plan, 04 (Sub Head) – Sarva Shiksha Abhiyan, 02 - General Component (Amount to be met from PSK), 31 - Grant-in-aid General, 2015-16 (Plan).

7. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, D-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115. On receipt of the sanction letter, the Principal Accounts Officer may issue an advice to the Reserve Bank of India (Central Accounts Sanction), Dehradun for affording credit to the balance of the State Government. The Principal Accounts Officer may forward a copy of the advice to the Accountant General and Finance Department of the State Government along with a copy to undersigned in the Department of School Education & Literacy. State Government shall send intimation regarding receipt of grant-in-aid to Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115.

8. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1108/2015/IFD dated 07.08.2015 and IF-II vide their Dy. No. 380/2015/IF-II dated 17.08.2015.

9. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

10. U.C. up to 2013-14 has been issued and hence no U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

No.F.10-3/2014-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy
EE.14 Section
*****

New Delhi, dated 7th October, 2014.

To

The Accounts Officer,
Pay and Accounts Office,
Department of School Education and Literacy,
Ministry of Human Resource Development,
Shastri Bhawan, New Delhi.

Sub:- Release of balance of 1st installment of grants under SSA for the year 2014-15 to SSA, Uttarakhand

Sir,

Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 212th Meeting held on 24th May,2014 approved the Annual Work Plan and Budget 2014-15 for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

2. In continuation of this Ministry's sanction letter of even number dated 23.05.2014, I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs. 8,49,000/- (Rupees Eight lakh forty nine thousand only)** under **Capital Head for Scheduled Tribe Component** as balance of 1st installment of grants for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV in Uttarakhand during the year 2014-15 to the SSA, Uttarakhand. With this release, the total releases will be Rs.15880.57 lakh for the year 2014-15.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of implementation of the SSA and the Financial & Procurement Manual for SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The amount sanctioned will be released to the State Government of Uttarakhand, who will disburse the entire funds through electronic transfer to **Account No. 1182101012885, Canara Bank, Anekant Palace, Rajpur Road, Dehrudun,** Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand immediately but not later than 15 days.

5. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2015.
(ii) It shall be utilized only for undertaking activities approved by the Project Approval Board of Department of School Education and Literacy, Govt. of India as per the Annual Work Plan for the year 2014-15.
(iii) The State Implementation Society (SIS) shall keep the amounts sanctioned for SSA/KGBV under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.
(iv) The State Government shall release their corresponding share (35%) against the approved AWP&B 2014-2015 to SSA, Uttarakhand in the bank account maintained para 3 above with the month of receipt of central share.
(v) SSA, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.
(vi) The grantee (SIS) shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year.
(vii) An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved programme duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year.

(MANJEET KUMAR)
Under Secretary/Junior Secretary
Tel: 011-23382/Govt. of India
E-mail: manjeet/Min. of HRD
Dept. of School Education & Literacy

(viii) The accounts and other records of the SSA Project Officer and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(ix) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme.

(x) No permanent posts shall be created under the SSA funds. Teacher posts shall be created by the State Government even where such posts are supported by SSA funding. Project positions for SSA implementation would be temporary, upto the duration of the project only.

(xiv) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if due has been transferred to the SSA, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure against central & state funds available with the SIS.

(xv) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xvi) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xvii) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

(xviii) The unspent balance of Central assistance released to State during the previous years will be adjusted while releasing the balance amount of first installment due to the State.

6. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 - Department of School Education & Literacy, 3601 (Major Head) – Grants-in-aid to State Govt., 02 (Sub-Major Head) – Grants for State Plan Scheme, 796 (Minor Head) – Scheduled Tribes Sub Plan, 04 (Sub Head) – Sarva Shiksha Abhiyan, 02 – General Component (Amount to be met from PSK), 35 – Grants for creation of Capital Assets, 2014-15 (Plan).

7. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, D-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115. On receipt of the sanction letter, the Principal Accounts Officer may issue an advice to the Reserve Bank of India (Central Accounts Sanction), Dehradun for affording credit to the balance of the State Government. The Principal Accounts Officer may forward a copy of the advice to the Accountant General and Finance Department of the State Government along with a copy to undersigned in the Department of School Education & Literacy. State Government shall send intimation regarding receipt of grant-in-aid to Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115.

8. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 4745/2014/IFD dated 29.09.2014 and IF-II vide their Dy. No. 993/2014/IF-II dated 01.10.2014.

9. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

10. U.C. up to 2012-13 has been issued and hence no U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

No.F.10-3/2014-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy
EE.14 Section
*****

New Delhi, dated 7th October, 2014.

To

The Accounts Officer,
Pay and Accounts Office,
Department of School Education and Literacy,
Ministry of Human Resource Development,
Shastri Bhawan, New Delhi.

Sub:- Release of balance of 1st installment of grants under SSA for the year 2014-15 to SSA, Uttarkhand

Sir,

Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 212th Meeting held on 24th May,2014 approved the Annual Work Plan and Budget 2014-15 for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

2. In continuation of this Ministry's sanction letter of even number dated 23.05.2014, I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs.65,92,000/- (Rupees sixty five lakh ninety two thousand only)** under **Capital Head for Schedule Caste Component** as balance of 1st installment of grants for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV in Uttarakhand during the year 2014-15 to the SSA, Uttarakhand. With this release, the total releases will be Rs.15880.57 lakh for the year 2014-15.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of implementation of the SSA and the Financial & Procurement Manual for SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The amount sanctioned will be released to the State Government of Uttarakhand, who will disburse the entire funds through electronic transfer to **Account No. 1182101012885, Canara Bank, Anekant Palace,Rajpur Road, Dehrudun,** Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand immediately but not later than 15 days.

5. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2015.
(ii) It shall be utilized only for undertaking activities approved by the Project Approval Board of Department of School Education and Literacy, Govt. of India as per the Annual Work Plan for the year 2014-15.
(iii) The State Implementation Society (SIS) shall keep the amounts sanctioned for SSA/KGBV under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.
(iv) The State Government shall release their corresponding share (35%) against the approved AWP&B 2014-2015 to SSA, Uttarakhand in the bank account maintained para 3 above with the month of receipt of central share.
(v) SSA, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.
(vi) The grantee (SIS) shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year.
(vii) An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved programme duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year.

(MANJEET KUMAR)

(viii) The accounts and other records of the SSA Project Officer and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(ix) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme.

(x) No permanent posts shall be created under the SSA funds. Teacher posts shall be created by the State Government even where such posts are supported by SSA funding. Project positions for SSA implementation would be temporary, upto the duration of the project only.

(xiv) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if due has been transferred to the SSA, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure against central & state funds available with the SIS.

(xv) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xvi) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xvii) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

(xviii) The unspent balance of Central assistance released to State during the previous years will be adjusted while releasing the balance amount of first installment due to the State.

6. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 - Department of School Education & Literacy, 3601 (Major Head) – Grants-in-aid to State Govt., 02 (Sub-Major Head) – Grants for State Plan Scheme, 789(Minor Head) - Special Component Plan for Scheduled Castes, 04 (Sub Head) – Sarva Shiksha Abhiyan, 02 – General Component (Amount to be met from PSK), 35 – Grants for creation of Capital Assets, 2014-15 (Plan).

7. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, D-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115. On receipt of the sanction letter, the Principal Accounts Officer may issue an advice to the Reserve Bank of India (Central Accounts Sanction), Dehradun for affording credit to the balance of the State Government. The Principal Accounts Officer may forward a copy of the advice to the Accountant General and Finance Department of the State Government along with a copy to undersigned in the Department of School Education & Literacy. State Government shall send intimation regarding receipt of grant-in-aid to Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115.

8. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 4745/2014/IFD dated 29.09.2014 and IF-II vide their Dy. No. 993/2014/IF-II dated 01.10.2014.

9. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

10. U.C. up to 2012-13 has been issued and hence no U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

(Manjeet Kumar)
अवर सचिव/Under Secretary
भारत सरकार/Govt. of India

No.F.10-3/2014-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy
EE.14 Section
*****

New Delhi, dated 7th October, 2014.

To

The Accounts Officer,
Pay and Accounts Office,
Department of School Education and Literacy,
Ministry of Human Resource Development,
Shastri Bhawan, New Delhi.

Sub:- Release of balance of 1st installment of grants under SSA for the year 2014-15 to SSA, Uttarkhand

Sir,

Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 212th Meeting held on 24th May,2014 approved the Annual Work Plan and Budget 2014-15 for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

2. In continuation of this Ministry's sanction letter of even number dated 23.05.2014, I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs.65,92,000/- (Rupees sixty five lakh ninety two thousand only)** under **Capital Head for Schedule Caste Component** as balance of 1st installment of grants for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV in Uttarakhand during the year 2014-15 to the SSA, Uttarakhand. With this release, the total releases will be Rs.15880.57 lakh for the year 2014-15.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of implementation of the SSA and the Financial & Procurement Manual for SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The amount sanctioned will be released to the State Government of Uttarakhand, who will disburse the entire funds through electronic transfer to **Account No. 1182101012885, Canara Bank, Anekant Palace,Rajpur Road, Dehrudun,** Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand immediately but not later than 15 days.

5. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2015.
(ii) It shall be utilized only for undertaking activities approved by the Project Approval Board of Department of School Education and Literacy, Govt. of India as per the Annual Work Plan for the year 2014-15.
(iii) The State Implementation Society (SIS) shall keep the amounts sanctioned for SSA/KGBV under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.
(iv) The State Government shall release their corresponding share (35%) against the approved AWP&B 2014-2015 to SSA, Uttarakhand in the bank account maintained para 3 above with the month of receipt of central share.
(v) SSA, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.
(vi) The grantee (SIS) shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year.
(vii) An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved programme duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year.

(MANJEET KUMAR)

(viii) The accounts and other records of the SSA Project Officer and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(ix) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme.

(x) No permanent posts shall be created under the SSA funds. Teacher posts shall be created by the State Government even where such posts are supported by SSA funding. Project positions for SSA implementation would be temporary, upto the duration of the project only.

(xiv) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if due has been transferred to the SSA, Uttarkhand and substantial progress has been made in expenditure against central & state funds available with the SIS.

(xv) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xvi) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xvii) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

(xviii) The unspent balance of Central assistance released to State during the previous years will be adjusted while releasing the balance amount of first installment due to the State.

6. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 - Department of School Education & Literacy, 3601 (Major Head) – Grants-in-aid to State Govt., 02 (Sub-Major Head) – Grants for State Plan Scheme, 186 (Minor Head) - Elementary Education -Sarva Shiksha Abhiyan, 01 (Sub Head) - General Component, 02 - Sarva Shiksha Abhiyan Component (Amount to be met from PSK), 35 – Grants for creation of Capital Assets, 2014-15 (Plan).

7. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, D-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115. On receipt of the sanction letter, the Principal Accounts Officer may issue an advice to the Reserve Bank of India (Central Accounts Sanction), Dehradun for affording credit to the balance of the State Government. The Principal Accounts Officer may forward a copy of the advice to the Accountant General and Finance Department of the State Government along with a copy to undersigned in the Department of School Education & Literacy. State Government shall send intimation regarding receipt of grant-in-aid to Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115.

8. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 4745/2014/IFD dated 29.09.2014 and IF-II vide their Dy. No. 993/2014/IF-II dated 01.10.2014.

9. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

10. U.C. up to 2012-13 has been issued and hence no U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

No.F.10-3/2014-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy
EE.14 Section
*****

New Delhi, dated 21st May, 2014.

To

The Accounts Officer,
Pay and Accounts Office,
Department of School Education and Literacy,
Ministry of Human Resource Development,
Shastri Bhawan, New Delhi.

Sub:- Release of ad-hoc (first) installment of grants under SSA for the year 2014-15 to SSA, Uttarkhand

Sir,

I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs.2,19,24,000/- (Rupees Two crore Ninteen lakh Twenty Four thousand only)** under **Capital Head for Schedule Caste Component** as ad-hoc (first) installment of grants for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV in Uttarakhand during the year 2014-15 to the SSA, Uttarakhand.

2. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of implementation of the SSA and the Financial & Procurement Manual for SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

3. The amount sanctioned will be released to the State Government of Uttarakhand, who will disburse the entire funds through electronic transfer to **Account No. 1182101012885, Canara Bank, Anekant Palace,Rajpur Road, Dehrudun,** Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand immediately but not later than 15 days.

4. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2015.
(ii) It shall be utilized only for undertaking activities approved by the Project Approval Board of Department of School Education and Literacy, Govt. of India as per the Annual Work Plan for the year 2014-15.
(iii) The State Implementation Society (SIS) shall keep the amounts sanctioned for SSA/KGBV under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.
(iv) The State Government shall release their corresponding share (35%) against the approved AWP&B 2014-2015 to SSA, Uttarakhand in the bank account maintained para 3 above with the month of receipt of central share.
(v) SSA, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.
(vi) The grantee (SIS) shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year.
(vii) An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved programme duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year.

(viii) The accounts and other records of the SSA Project Officer and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(ix) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme.

(x) No permanent posts shall be created under the SSA funds. Teacher posts shall be created by the State Government even where such posts are supported by SSA funding. Project positions for SSA implementation would be temporary, upto the duration of the project only.

(xiv) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if due has been transferred to the SSA, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure against central & state funds available with the SIS.

(xv) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xvi) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xvii) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

(xviii) The unspent balance of Central assistance released to State during the previous years will be adjusted while releasing the balance amount of first installment due to the State.

5. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 - Department of School Education & Literacy, 3601 (Major Head) - General Education, 02 (Sub-Major Head) - Elementary Education, 789(Minor Head) - Sarva Shiksha Abhiyan, 04 (Sub Head) – Scheduled Caste Component, 01 - Sarva Shiksha Abhiyan (Amount to be met from GBS), 35 - Grant-in-aid Capital, 2014-15 (Plan).

6. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, D-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115. On receipt of the sanction letter, the Principal Accounts Officer may issue an advice to the Reserve Bank of India (Central Accounts Sanction), Dehradun for affording credit to the balance of the State Government. The Principal Accounts Officer may forward a copy of the advice to the Accountant General and Finance Department of the State Government along with a copy to undersigned in the Department of School Education & Literacy. State Government shall send intimation regarding receipt of grant-in-aid to Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115.

7. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1734/2014/IFD dated 30.04.2014 and IF-II vide their Dy. No. 520/2014/IF-II dated 15.05.2014.

8. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

9. U.C. up to 2012-13 has been issued and hence no U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

Copy forwarded to:

1. State Project Director, Uttarakhand, Dehradun.
2. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Dehradun
3. The Secretary (Primary & Secondary Education), Government of Uttarakhand, Dehradun.
4. The Drawing and disbursing Officer (Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy in duplicate for drawal and disbursement electronically.
5. Office of the Director General of Audit-I Central Revenue OAD-II Section, AGCR Building I.P. Estate, New Delhi 110002.
6. The Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.
7. The Accountant General (A&E), Govt. of Uttarakhand, Dehradun.
8. IF-2 Section/E.C. Unit/IFD/EE-3 Section.
9. Guard File.

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

No.F.10-3/2014-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy
EE.14 Section
*****

New Delhi, dated 21st May, 2014.

The Accounts Officer,
Pay and Accounts Office,
Department of School Education and Literacy,
Ministry of Human Resource Development,
Shastri Bhawan, New Delhi.

Sub:- Release of ad-hoc (first) installment of grants under SSA for the year 2014-15 to SSA, Uttarakhand

Sir,

I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs. 28,25,000/- (Rupees Twenty Eight lakh Twenty Five thousand only)** under **Capital Head for Scheduled Tribe Component** as ad-hoc (first) installment of grants for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV in Uttarakhand during the year 2014-15 to the SSA, Uttarakhand.

2. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of implementation of the SSA and the Financial & Procurement Manual for SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

3. The amount sanctioned will be released to the State Government of Uttarakhand, who will disburse the entire funds through electronic transfer to **Account No. 1182101012885, Canara Bank, Anekant Palace,Rajpur Road, Dehrudun,** Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand immediately but not later than 15 days.

4. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2015.
(ii) It shall be utilized only for undertaking activities approved by the Project Approval Board of Department of School Education and Literacy, Govt. of India as per the Annual Work Plan for the year 2014-15.
(iii) The State Implementation Society (SIS) shall keep the amounts sanctioned for SSA/KGBV under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.
(iv) The State Government shall release their corresponding share (35%) against the approved AWP&B 2014-2015 to SSA, Uttarakhand in the bank account maintained para 3 above with the month of receipt of central share.
(v) SSA, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.
(vi) The grantee (SIS) shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year.
(vii) An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved programme duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year.

(viii) The accounts and other records of the SSA Project Officer and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(ix) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme.

(x) No permanent posts shall be created under the SSA funds. Teacher posts shall be created by the State Government even where such posts are supported by SSA funding. Project positions for SSA implementation would be temporary, upto the duration of the project only.

(xiv) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if due has been transferred to the SSA, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure against central & state funds available with the SIS.

(xv) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xvi) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xvii) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

(xviii) The unspent balance of Central assistance released to State during the previous years will be adjusted while releasing the balance amount of first installment due to the State.

5. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 - Department of School Education & Literacy, 3601 (Major Head) - General Education, 02 (Sub-Major Head) - Elementary Education, 796 (Minor Head) - Sarva Shiksha Abhiyan, 04 (Sub Head) – Scheduled Tribe Component, 01 - Sarva Shiksha Abhiyan (Amount to be met from GBS), 35 - Grant-in-aid Capital, 2014-15 (Plan).

6. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, D-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115. On receipt of the sanction letter, the Principal Accounts Officer may issue an advice to the Reserve Bank of India (Central Accounts Sanction), Dehradun for affording credit to the balance of the State Government. The Principal Accounts Officer may forward a copy of the advice to the Accountant General and Finance Department of the State Government along with a copy to undersigned in the Department of School Education & Literacy. State Government shall send intimation regarding receipt of grant-in-aid to Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115.

7. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1734/2014/IFD dated 30.04.2014 and IF-II vide their Dy. No. 520/2014/IF-II dated 15.05.2014.

8. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

9. U.C. up to 2012-13 has been issued and hence no U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

Copy forwarded to:

1. State Project Director, Uttarakhand, Dehradun.
2. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Dehradun
3. The Secretary (Primary & Secondary Education), Government of Uttarakhand, Dehradun.
4. The Drawing and disbursing Officer (Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy in duplicate for drawal and disbursement electronically.
5. Office of the Director General of Audit-I Central Revenue OAD-II Section, AGCR Building I.P. Estate, New Delhi 110002.
6. The Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.
7. The Accountant General (A&E), Govt. of Uttarakhand, Dehradun.
8. IF-2 Section/E.C. Unit/IFD/EE-3 Section.
9. Guard File.

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

No. F. 10-5/2013-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy

New Delhi, the 6th May,2013.

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan
New Delhi

Subject:- Release of 1st tranche of 1st installment of Central share under SSA for the year 2013-14(Plan) to SSA, Uttarakhand.

Sir,

The Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 193rd Meeting held on 25th February,2013 approved the Annual Work Plan ad Budget 2013-14 for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

2. I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs.1,72,39,000/- (Rupees one crore seventy two lakh thirty nine thousand only)** under **Grants-in-aid For creation of Capital Assets Head** as 1st tranche of 1st installment of Central share for implementation of SSA, NPEGEL, KGBV within the ceiling of PAB approved outlay for 2013-14 to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun. With this release, the total releases will be Rs.9513.30 lakh for the year 2013-14.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The money sanctioned herein should be spent on priority to provide norms and standards as laid down in the schedule to RTE Act, 2009.

5. The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

6. The State will maintain separate accounts for grants released under Grant-in-aid General and Grants for creation of Capital Assets. Further at the end of the financial year State will provide expenditure and unspent balance on General and Capital object head separately.

(मनोज कुमार)
MANOJ KUMAR
Under Secretary
Govt. of India

7. The amount sanctioned will be drawn by the Drawing and Disbursing Officer(Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Government of India New Delhi on a grant-in-aid bill and disbursed to the grantee through electronic/telegraphic transfer of fund to the State Project Director, Uttarkhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand during the current financial year 2013-14. The details of bank account of the society is as follow:

Account No. 1182101012885
Canara Bank, Anekant Palace
Rajpur Road, Dehrudun

8. Authorisation letter received from the payee is enclosed for making the e-payment in favour of Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

9. The grant shall be subject to the following conditions:

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2014 and shall be utilized within a reasonable period from the date of drawl.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities proposed in the Work Plan for the year 2013-14 and as approved by the Project Approval Board, and by the Government of India on the basis norms of expenditure.

(iii) The assets, if any, acquired wholly or substantially out of this grant, should not, without the prior sanction of the Government of India, be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant has been sanctioned.

(iv) The grantee shall maintain a separate and proper account of the expenditure incurred out of the grant and the accounts so maintained shall be open to audit by the Comptroller & Auditor General of India or any authority deputed by him for the purpose as per rules.

(v) The State Implementation Society shall keep the amounts sanctioned for SSA/NPEGEL under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(vi) The State Government shall release their correspondence share (35%) against AWP&B 2013-14 to Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand in time as per stipulation mentioned in the Framework of the scheme besides releasing the entire accumulated deficit of State share since 2000-2001. Subsequent installment of grant would be sanctioned only after the entire backlog of State share including the one due against the current year approved budget is released by the State Government to the State Society.

(vii) Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(viii) The amount sanctioned for a district shall be made available to the district level institution authorized for the implementation of SSA. Individual districts shall spend the amount given to them on the items proposed by them in the District Plans for the year 2013-14 and as approved by the PAB, and in accordance with other general principles and Framework of the scheme and the terms of this sanction.

Kumar

(मनजीत कुमार)
MANJEET KUMAR

(ix) The grant shall be utilized only for undertaking activities as approved by the Government of India on the basis of norms of expenditure.

(x) State Mission Authority of Education for All, Uttarakhand shall fully implement the Official Language Policy of the Union Government i.e. It shall full comply with Official Language Act, 1963 and Office Language (used for the official purpose of the Union) Rules, 1976 etc.

(xi) The grantee shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year. An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved project duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year. The unspent balance, if any shall be taken into account before funds or subsequent years are released.

(xii) A register of assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be acquired should be sent to this Ministry not later than one month from the close of the financial year. Such copies should continue to be furnished even after Government grant ceased. The Statements shall relate to all assets created wholly or substantially out of the Governmental grant upto the end of the period to which the return relates.

(xiii) The accounts and other records of the Project Officers and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(xiv) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme and reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(xv) There shall be no appointment of permanent staff, except additional teachers only as per SSA norms. The existing staff of the State Government should be optimally utilized. The principal work of project implementation shall be on the mainstream administrative establishment at State and district levels. However, in case there is any need to appoint contractual staff for a limited period for the performance of specialised jobs for which expertise is not available with them. Such contractual staff may only be hired by the district/block/village levels only and the cost maintained within 6% management cost as envisaged under the scheme.

(xvi) The guidelines issued by the Government of India from time to time regarding monitoring management and financial control and other procedure would be followed in the execution of the Project.

(xvii) The State Government should give a written commitment for meeting its share of the SSA/NPEGEL outlay.

(xviii) First installment of the State share should also be released to the Society within one month of the release of central share to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

(xix) Teachers appointed against posts created through SSA funds should be made accountable to the VEC for at least salary payment. The latter would monitor the attendance before releasing the salary.

(xx) VECs or equivalent bodies should be constituted and accounts opened to incur expenditure under teachers grant, civil works, maintenance grants, school grants and other such expenditure which has to be incurred only through these bodies as per SSA norms and should be utilized within one month of its release.

Uma

(xxi) State Government will maintain their level of investment in elementary education as in 1999-2000 and give the details of this to Government of India before the release of installment. The contribution as State share for SSA will be over and above this investment.

(xxii) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if any, has been transferred to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure as far as money already released is concerned.

(xxiii) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render toe grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xxiv) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xxv) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

10. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 Department of School Education and Literacy; Major Head 2202; General Education –01-Elementary Education -789- Special Component Plan for Scheduled Caste - 02- Sarva Shiksha Abhiyan - 02.02 General Component (PSK) - 02.02.35 Grant-in-aid for creation of capital assets 2012-13 (Plan).

11. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 2472/2013/IFD dated 26.04.2013 and IF-II vide their Dy. No.757/2013/IF-II dated 30.04.2013.

12. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

13. No U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23073542

Copy forwarded to:

1. State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand The grantee institution is required to submit the under mentioned documents as per terms and conditions of the sanction letter to enable the Ministry to release the grant:-

   (a) Bond for **Rs.9513.30 lakh** in revised format.
   (b) Authorisation letter as in the revised format.

2. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand , Dehradun.

3. The Principal Secretary (Education), Government of Uttarakhand, Sachicalaya, Dehradun-248001, Uttarakahnd. The State Government is requested to kindly furnish written commitment as per para 6 (vi) of the sanction.

4. The Drawing and disbursing Officer (Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy in duplicate for drawal and disbursement electronically.

5. Office of the Director General of Audit-I Central Revenue OAD-II Section, AGCR Building I.P. Estate, New Delhi 110002.

6. The Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.

7. The Accountant General, Uttarakhand, Dehradun

8. IF-2 Section/E.C. Unit/IFD/EE-15 section.

9. Shri Shailander Sharma, Chief Consultant TSG Ed-CIL New Delhi.

10. Guard File.

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

No. F. 10-5/2012-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy

New Delhi, the 5th November,2012

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan
New Delhi

Subject:- Release of 2nd installment of Central share under SSA for the year 2012-13 (Plan) to SSA, Uttarakhand.

Sir,

In continuation of this Department's sanction letter of even number dated 18.07.2012, I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs.74,58,000/- (Rupees seventy four lakh fifty eight thousand only)** under **Grants-in-aid for creation of capital assets head** as 2nd installment of Central share release for implementation of SSA and its component during the year 2012-13 to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun. With this release, the total releases will be Rs.17941.10 lakh as ad-hoc grants for the year 2012-13.

2. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

3. The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

4. The State will maintain separate accounts for grants released under Grant-in-aid General and Grants for creation of Capital Assets. Further at the end of the financial year State will provide expenditure and unspent balance on General and Capital object head separately.

5. The amount sanctioned will be drawn by the Drawing and Disbursing Officer(Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Government of India New Delhi on a grant-in-aid bill and disbursed to the grantee through electronic/telegraphic transfer of fund to the State Project Director, Uttarkhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand during the current financial year 2012-13. The details of bank account of the society is as follow:

Account No. 1182101012885
Canara Bank, Anekant Palace
Rajpur Road, Dehrudun

(मनजीत कुमार)
MANJEET KUMAR)
Under Secretary
Min. of H.R.D.
School Education & Literacy
Govt. of India
New Delhi

.../..

6. Authorisation letter received from the payee is enclosed for making the e-payment in favour of Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

7. **The grant shall be subject to the following conditions**:

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2013 and shall be utilized within a reasonable period from the date of drawl.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities proposed in the Work Plan for the year 2012-13 and as approved by the Project Approval Board, and by the Government of India on the basis norms of expenditure.

(iii) The assets, if any, acquired wholly or substantially out of this grant, should not, without the prior sanction of the Government of India, be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant has been sanctioned.

(iv) The grantee shall maintain a separate and proper account of the expenditure incurred out of the grant and the accounts so maintained shall be open to audit by the Comptroller & Auditor General of India or any authority deputed by him for the purpose as per rules.

(v) The State Implementation Society shall keep the amounts sanctioned for SSA/NPEGEL under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(vi) The State Government shall release their correspondence share (35%) against AWP&B 2012-13 to Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand in time as per stipulation mentioned in the Framework of the scheme besides releasing the entire accumulated deficit of State share since 2000-2001. Subsequent installment of grant would be sanctioned only after the entire backlog of State share including the one due against the current year approved budget is released by the State Government to the State Society.

(vii) Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(viii) The amount sanctioned for a district shall be made available to the district level institution authorized for the implementation of SSA. Individual districts shall spend the amount given to them on the items proposed by them in the District Plans for the year 2012-13 and as approved by the PAB, and in accordance with other general principles and Framework of the scheme and the terms of this sanction.

(ix) The grant shall be utilized only for undertaking activities as approved by the Government of India on the basis of norms of expenditure.

(x) State Mission Authority of Education for All, Uttarakhand shall fully implement the Official Language Policy of the Union Government i.e. It shall full comply with Official Language Act, 1963 and Office Language (used for the official purpose of the Union) Rules, 1976 etc.

(xi) The grantee shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year. An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved project duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year. The unspent balance, if any shall be taken into account before funds or subsequent years are released.

(MANJEET KUMAR)
Under Secretary
Min. of H.R.D.
Dept. of School Education & Literacy
Govt. of India
New Delhi

.../..

(xii) A register of assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be acquired should be sent to this Ministry not later than one month from the close of the financial year. Such copies should continue to be furnished even after Government grant ceased. The Statements shall relate to all assets created wholly or substantially out of the Governmental grant upto the end of the period to which the return relates.

(xiii) The accounts and other records of the Project Officers and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(xiv) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme and reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(xv) There shall be no appointment of permanent staff, except additional teachers only as per SSA norms. The existing staff of the State Government should be optimally utilized. The principal work of project implementation shall be on the mainstream administrative establishment at State and district levels. However, in case there is any need to appoint contractual staff for a limited period for the performance of specialised jobs for which expertise is not available with them. Such contractual staff may only be hired by the district/block/village levels only and the cost maintained within 6% management cost as envisaged under the scheme.

(xvi) The guidelines issued by the Government of India from time to time regarding monitoring management and financial control and other procedure would be followed in the execution of the Project.

(xvii) The State Government should give a written commitment for meeting its share of the SSA/NPEGEL outlay.

(xviii) First installment of the State share should also be released to the Society within one month of the release of central share to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

(xix) Teachers appointed against posts created through SSA funds should be made accountable to the VEC for at least salary payment. The latter would monitor the attendance before releasing the salary.

(xx) VECs or equivalent bodies should be constituted and accounts opened to incur expenditure under teachers grant, civil works, maintenance grants, school grants and other such expenditure which has to be incurred only through these bodies as per SSA norms and should be utilized within one month of its release.

(xxi) State Government will maintain their level of investment in elementary education as in 1999-2000 and give the details of this to Government of India before the release of installment. The contribution as State share for SSA will be over and above this investment.

(xxii) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if any, has been transferred to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure as far as money already released is concerned.

(xxiii) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render toe grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

.../..

(मनजीत कुमार)
MANJEET KUMAR
Under Secretary
भारत सरकार/Min. of H.R.D.
School Education & Literacy
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(xxiv) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xxv) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

8. The expenditure will be debitable to Demand No. 58 Department of School Education and Literacy; Major Head 2202; General Education –01-Elementary Education -796-Scheduled Tribe sub plans - 03- Sarva Shiksha Abhiyan - 03.02 General Component (PSK) - 03.02.35 Grant-in-aid for creation of capital assets 2012-13 (Plan).

9. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 6980/12/IFD dated 18.10.2012 and IF-II vide their Dy. No.1388 /2012/IF-II dated 19.10.2012.

10. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

11. No U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23384582

Dte. School Education & Literacy
Govt. of India
New Delhi

Copy forwarded to:

1. State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand The grantee institution is required to submit the under mentioned documents as per terms and conditions of the sanction letter to enable the Ministry to release the grant:-

   (a) Bond for **Rs. 9052.00 lakh** in revised format.
   (b) Authorisation letter as in the revised format.

2. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand , Dehradun.

3. The Principal Secretary (Education), Government of Uttarakhand, Sachicalaya, Dehradun-248001, Uttarakahnd. The State Government is requested to kindly furnish written commitment as per para 6 (vi) of the sanction.

4. The Drawing and disbursing Officer (Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy in duplicate for drawal and disbursement electronically.

5. Office of the Director General of Audit-I Central Revenue OAD-II Section, AGCR Building I.P. Estate, New Delhi 110002.

6. The Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.

7. The Accountant General, Uttarakhand, Dehradun

8. IF-2 Section/E.C. Unit/IFD/EE-15 section.

9. Shri Shailander Sharma, Chief Consultant TSG Ed-CIL New Delhi.

10. Guard File.

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

Under Secretary
M.H.R.D.
Department of School Education & Literacy
Govt. of India
New Delhi

सॅ0 701 /XXIV(1)/2012–03/2012

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3409
डाक प्राप्ति दिनांक 15/09/12

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
नन्दूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनांकः।५ सितम्बर, 2012

विषयः **वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–रा0प0नि0/1301/लेखा–2/राज्यांश/2012–13, दिनांक 08.08.2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु योजनाओं पर व्यय हेतु संलग्नक–01 में उल्लिखित विवरणानुसार योजनागत के अनुदान–11 लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा तथा अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय में कुल धनराशि रू0 26,02,62,000–00(रूपये छब्बीस करोड़ दो लाख बासठ हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) वित्त विभाग के संलग्न शासनादेश सॅ0 321/xxvii(1)/2012, दिनांक 19.6.2012 एवं शासनादेश सॅ0 193/xxvii(1)/2012, दिनॉक 30.3.2012 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आंवटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

F.C.
14.09.12
AAO (Finance & Accounts)
14.09.12

(8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा व लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

03– यह ओदश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 78(P)/XXVII(3)/2012-13 दिनांक 10.9.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

सँ0 701 (i)/XXIV(1)/2012–03/2012 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0आर0 सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–70) /XXIV(1)/2012-03/2012 दिनांक 4 सितम्बर, 2012 का संलग्नक–1।

(धनराशि रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक		आय–व्ययक 2012–13 में कुल प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य) – आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं		
0104	सर्व शिक्षा अभियान (35 प्रतिशत राज्यांश)		
	20– सहायक/अनुदान/अंशदान/राज सहायता	14834.82	2459.97
अनुदान संख्या–11 – आयोजनागत			
4202	शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारम्भिक शिक्षा		
03	प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण		
04	सर्व शिक्षा अभियान		
	35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	2875.94	142.65
कुल योग (अनुदान संख्या–11 के दोनों लेखाशीर्षकों सहित)			2602.62

(रूपये छब्बीस करोड दो लाख बासठ हजार मात्र)

(आर0आर0 सिंह)
अनु सचिव।

सँ0 1000 /XXIV(1)/2012–03/2012

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु,
प्रभारी सचिव ,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

4614
15/12/12

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)

देहरादून दिनांकः 07 दिसम्बर, 2012

विषयः **वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम संचालन हेतु केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–रा0प0का0/2231/लेखा–2/राज्यांश/2012–13 दिनांक 12.11.2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्यांश की देयता मद में संलग्नक–01 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान –11 (सामान्य), अनुदान सँ0 30 (एस0सी0एस0पी0)एवं अनुदान सँ0 31 (टी0एस0पी0) में कुल धनराशि **रू0 48,74,15,000–00 (रूपये अड़तालीस करोड़ चौहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र)** आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) वित्त विभाग के शासनादेश सँ0 321/xxvii(1)/2012, दिनांक 19.6.2012 एवं शासनादेश सँ0 193/xxvii(1)/2012, दिनॉक 30.3.2012 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आंवटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

ADD/FC 13/12/12 FO 14/12/12 A/C DOW 13/12

(8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा व 4202–01 के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 147/XXVII(3)/2012-13 दिनांक 04.12.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 सुधांशु)
प्रभारी सचिव।

सँ0 1000 (i)/XXIV(1)/2012–03/2012 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0आर0 सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–1880/XXIV(1)/2012-03/2012 दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 का संलग्नक।

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक		आय–व्ययक 2012–13 में कुल प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य) –आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं		
0104	सर्व शिक्षा अभियान (35 प्रतिशत राज्यांश)		
	20– सहायक/अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1483482	261219
अनुदान संख्या–11–आयोजनागत			
4202	शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारम्भिक शिक्षा		
04	सर्व शिक्षा अभियान		
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	287594	83871
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)–आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं		
0101	सर्व शिक्षा अभियान (35 प्रतिशत राज्यांश)		
	20– सहायक/अनुदान/अंशदान/राज सहायता	390729	95227
अनुदान संख्या–30–(एस0सी0एस0पी0)–आयोजनागत			
4202	शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारम्भिक शिक्षा		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें		
0101	सर्व शिक्षा अभियान (35 प्रतिशत राज्यांश)		
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	85770	30575
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)–आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं		
0101	सर्व शिक्षा अभियान		
	20– सहायक/अनुदान/अंशदान/राज सहायता	82259	12507
अनुदान संख्या–31–(टी0एस0पी0)–आयोजनागत			
4202	शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारम्भिक शिक्षा		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें		
0101	सर्व शिक्षा अभियान (35 प्रतिशत राज्यांश)		
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	18057	4016
	कुल योग (अनुदान सॅ0 11 + 30 + 31)	2347891	487415

(रूपये अड़तालीस करोड़ चौहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र)

(आर0 आर0 सिंह)
अनुसचिव

No. F. 10-5/2013-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy

New Delhi, the 6th May,2013

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan
New Delhi

Subject:- Release of 1st tranche of 1st installment of Central share under SSA for the year 2013-14(Plan) to SSA, Uttarakhand.

F.C.

Sir,

The Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 193rd Meeting held on 25th February,2013 approved the Annual Work Plan ad Budget 2013-14 for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

06/06/13

2. I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs.62,95,88,000/- (Rupees sixty two crore ninety five lakh eighty eight thousand only)** under **Grants-in-aid General Head** as 1st tranche of 1st installment of Central share for implementation of SSA, NPEGEL, KGBV relating to child entitlements like textbooks, uniform, school grants, etc. within the ceiling of PAB approved outlay for 2013-14 to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun. With this release, the total releases will be Rs.9513.30 lakh for the year 2013-14.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

5. The money sanctioned herein should be spent on priority to provide norms and standards as laid down in the schedule to RTE Act, 2009.

6. The State will maintain separate accounts for grants released under Grant-in-aid General and Grants for creation of Capital Assets. Further at the end of the financial year State will provide expenditure and unspent balance on General and Capital object head separately.

(राजीव कुमार)
(RAJEET KUMAR)
Under Secretary
Ministry of H.R.D.
Department of School Education and Literacy
Shastri Bhavan, New Delhi

The amount sanctioned will be drawn by the Drawing and Disbursing Officer(Grants), ry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, nment of India New Delhi on a grant-in-aid bill and disbursed to the grantee through onic/telegraphic transfer of fund to the State Project Director, Uttarkhand Sabhi Ke Liye sha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand during the current financial year 2013-14. The ils of bank account of the society is as follow:

Account No. 1182101012885
Canara Bank, Anekant Palace
Rajpur Road, Dehrudun

8. Authorisation letter received from the payee is enclosed for making the e-payment in favour of Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

9. The grant shall be subject to the following conditions:

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2014 and shall be utilized within a reasonable period from the date of drawl.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities proposed in the Work Plan for the year 2013-14 and as approved by the Project Approval Board, and by the Government of India on the basis norms of expenditure.

(iii) The assets, if any, acquired wholly or substantially out of this grant, should not, without the prior sanction of the Government of India, be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant has been sanctioned.

(iv) The grantee shall maintain a separate and proper account of the expenditure incurred out of the grant and the accounts so maintained shall be open to audit by the Comptroller & Auditor General of India or any authority deputed by him for the purpose as per rules.

(v) The State Implementation Society shall keep the amounts sanctioned for SSA/NPEGEL under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(vi) The State Government shall release their correspondence share (35%) against AWP&B 2013-14 to Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand in time as per stipulation mentioned in the Framework of the scheme besides releasing the entire accumulated deficit of State share since 2000-2001. Subsequent installment of grant would be sanctioned only after the entire backlog of State share including the one due against the current year approved budget is released by the State Government to the State Society.

(vii) Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(viii) The amount sanctioned for a district shall be made available to the district level institution authorized for the implementation of SSA. Individual districts shall spend the amount given to them on the items proposed by them in the District Plans for the year 2013-14 and as approved by the PAB, and in accordance with other general principles and Framework of the scheme and the terms of this sanction.

The grant shall be utilized only for undertaking activities as approved by the Government of India on the basis of norms of expenditure.

State Mission Authority of Education for All, Uttarakhand shall fully implement the Official Language Policy of the Union Government i.e. It shall full comply with Official Language Act, 1963 and Office Language (used for the official purpose of the Union) Rules, 1976 etc.

The grantee shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year. An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved project duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year. The unspent balance, if any shall be taken into account before funds or subsequent years are released.

i) A register of assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be acquired should be sent to this Ministry not later than one month from the close of the financial year. Such copies should continue to be furnished even after Government grant ceased. The Statements shall relate to all assets created wholly or substantially out of the Governmental grant upto the end of the period to which the return relates.

xiii) The accounts and other records of the Project Officers and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(xiv) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme and reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(xv) There shall be no appointment of permanent staff, except additional teachers only as per SSA norms. The existing staff of the State Government should be optimally utilized. The principal work of project implementation shall be on the mainstream administrative establishment at State and district levels. However, in case there is any need to appoint contractual staff for a limited period for the performance of specialised jobs for which expertise is not available with them. Such contractual staff may only be hired by the district/block/village levels only and the cost maintained within 6% management cost as envisaged under the scheme.

(xvi) The guidelines issued by the Government of India from time to time regarding monitoring, management and financial control and other procedure would be followed in the execution of the Project.

(xvii) The State Government should give a written commitment for meeting its share of the SSA/NPEGEL outlay.

(xviii) First installment of the State share should also be released to the Society within one month of the release of central share to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

(xix) Teachers appointed against posts created through SSA funds should be made accountable to the VEC for at least salary payment. The latter would monitor the attendance before releasing the salary.

(xx) VECs or equivalent bodies should be constituted and accounts opened to incur expenditure under teachers grant, civil works, maintenance grants, school grants and other such expenditure which has to be incurred only through these bodies as per SSA norms and should be utilized within one month of its release.

Uma

(Uma Gupta)
Under Secretary
Tel. No./Under Secretary
Fax No./Addl. or H.R.D.
Dy. Secretary Retd.
Education & Literacy
Govt. of India
Delhi

State Government will maintain their level of investment in elementary education as in 1999-2000 and give the details of this to Government of India before the release of installment. The contribution as State share for SSA will be over and above this investment.

(xxii) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if any, has been transferred to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure as far as money already released is concerned.

(xxiii) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render toe grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xxiv) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xxv) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

10. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 Department of School Education and Literacy; Major Head 2202; General Education -01-Elementary Education -111- Sarva Shiksha Abhiyan - 01-General Component- 01.01 - Sarva Shiksha Abhiyan (GBS) - 01.01.31 Grant-in-aid General 2013-14 (Plan).

11. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 2472/2013/IFD dated 26.04.2013 and IF-II vide their Dy. No.757/2013/IF-II dated 30.04.2013.

12. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

13. No U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23073542

Dept. of School Education & Literacy
D/o School Education & Literacy/Govt. of India
New Delhi

No. F. 10-5/2013-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy

New Delhi, the 27th March,2014.

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan
New Delhi

Subject:- Release of 4th installment of Central share under SSA for the year 2013-14(Plan) to SSA, Uttarakhand.

Sir,

The Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 193rd Meeting held on 25th February,2013 approved the Annual Work Plan ad Budget 2013-14 for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

2. In continuation of this Ministry's sanction letter of even number dated 18.2.2014, I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs.1,98,46,000/- (Rupees one crore ninety eight lakh forty six thousand only)** under **Grants-in-aid For creation of Capital Assets Head** as 4th installment of Central share for implementation of SSA, NPEGEL, KGBV within the ceiling of PAB approved outlay for 2013-14 to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun. With this release, the total releases will be Rs.22043.37 lakh for the year 2013-14.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The money sanctioned herein should be spent on priority to provide norms and standards as laid down in the schedule to RTE Act, 2009.

5. The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

6. The State will maintain separate accounts for grants released under Grant-in-aid General and Grants for creation of Capital Assets. Further at the end of the financial year State will provide expenditure and unspent balance on General and Capital object head separately.

7. The amount sanctioned will be drawn by the Drawing and Disbursing Officer(Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Government of India New Delhi on a grant-in-aid bill and disbursed to the grantee through electronic/telegraphic transfer of fund to the State Project Director, Uttarkhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand during the current financial year 2013-14. The details of bank account of the society is as follow:

Account No. 1182101012885
Canara Bank, Anekant Palace
Rajpur Road, Dehrudun

8. Authorisation letter received from the payee is enclosed for making the e-payment in favour of Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

9. The grant shall be subject to the following conditions:

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2014 and shall be utilized within a reasonable period from the date of drawl.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities proposed in the Work Plan for the year 2013-14 and as approved by the Project Approval Board, and by the Government of India on the basis norms of expenditure.

(iii) The assets, if any, acquired wholly or substantially out of this grant, should not, without the prior sanction of the Government of India, be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant has been sanctioned.

(iv) The grantee shall maintain a separate and proper account of the expenditure incurred out of the grant and the accounts so maintained shall be open to audit by the Comptroller & Auditor General of India or any authority deputed by him for the purpose as per rules.

(v) The State Implementation Society shall keep the amounts sanctioned for SSA/NPEGEL under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(vi) The State Government shall release their correspondence share (35%) against AWP&B 2013-14 to Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand in time as per stipulation mentioned in the Framework of the scheme besides releasing the entire accumulated deficit of State share since 2000-2001. Subsequent installment of grant would be sanctioned only after the entire backlog of State share including the one due against the current year approved budget is released by the State Government to the State Society.

(vii) Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(viii) The amount sanctioned for a district shall be made available to the district level institution authorized for the implementation of SSA. Individual districts shall spend the amount given to them on the items proposed by them in the District Plans for the year 2013-14 and as approved by the PAB, and in accordance with other general principles and Framework of the scheme and the terms of this sanction.

(ix) The grant shall be utilized only for undertaking activities as approved by the Government of India on the basis of norms of expenditure.

(x) State Mission Authority of Education for All, Uttarakhand shall fully implement the Official Language Policy of the Union Government i.e. It shall full comply with Official Language Act, 1963 and Office Language (used for the official purpose of the Union) Rules, 1976 etc.

(xi) The grantee shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year. An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved project duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year. The unspent balance, if any shall be taken into account before funds or subsequent years are released.

(xii) A register of assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be acquired should be sent to this Ministry not later than one month from the close of the financial year. Such copies should continue to be furnished even after Government grant ceased. The Statements shall relate to all assets created wholly or substantially out of the Governmental grant upto the end of the period to which the return relates.

(xiii) The accounts and other records of the Project Officers and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(xiv) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme and reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(xv) There shall be no appointment of permanent staff, except additional teachers only as per SSA norms. The existing staff of the State Government should be optimally utilized. The principal work of project implementation shall be on the mainstream administrative establishment at State and district levels. However, in case there is any need to appoint contractual staff for a limited period for the performance of specialised jobs for which expertise is not available with them. Such contractual staff may only be hired by the district/block/village levels only and the cost maintained within 6% management cost as envisaged under the scheme.

(xvi) The guidelines issued by the Government of India from time to time regarding monitoring management and financial control and other procedure would be followed in the execution of the Project.

(xvii) The State Government should give a written commitment for meeting its share of the SSA/NPEGEL outlay.

(xviii) First installment of the State share should also be released to the Society within one month of the release of central share to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

(xix) Teachers appointed against posts created through SSA funds should be made accountable to the VEC for at least salary payment. The latter would monitor the attendance before releasing the salary.

(xx) VECs or equivalent bodies should be constituted and accounts opened to incur expenditure under teachers grant, civil works, maintenance grants, school grants and other such expenditure which has to be incurred only through these bodies as per SSA norms and should be utilized within one month of its release.

(xxi) State Government will maintain their level of investment in elementary education as in 1999-2000 and give the details of this to Government of India before the release of installment. The contribution as State share for SSA will be over and above this investment.

(xxii) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if any, has been transferred to the Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure as far as money already released is concerned.

(xxiii) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render toe grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xxiv) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xxv) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

10. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 Department of School Education and Literacy; Major Head 2202; General Education –01-Elementary Education -789- Special Component Plan for Scheduled Caste - 02- Sarva Shiksha Abhiyan - 02.02 General Component (PSK) - 02.02.35 Grant-in-aid for creation of capital assets 2013-14 (Plan).

11. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1317/2014/IFD dated 21.03.2014 and IF-II vide their Dy. No.377/2014/IF-II dated 25.03.2014.

12. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

13. No U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23073542

Copy forwarded to:

1. Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand. The grantee institution is required to submit the under mentioned documents as per terms and conditions of the sanction letter to enable the Ministry to release the grant:-

   (a) Bond for **Rs.772.21 lakh** in revised format.
   (b) Authorisation letter as in the revised format.

2. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand , Dehradun.

3. The Principal Secretary (Education), Government of Uttarakhand, Sachicalaya, Dehradun-248001, Uttarakahnd. The State Government is requested to kindly furnish written commitment as per para 6 (vi) of the sanction.

4. The Drawing and disbursing Officer (Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy in duplicate for drawal and disbursement electronically.

5. Office of the Director General of Audit-I Central Revenue OAD-II Section, AGCR Building I.P. Estate, New Delhi 110002.

6. The Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.

7. The Accountant General, Uttarakhand, Dehradun

8. IF-2 Section/E.C. Unit/IFD/EE-15 section.

9. Chief Consultant TSG Ed-CIL New Delhi.

10. Guard File.

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

सँ0 ___ /XXIV(1)/2013–16/2013

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2945 (2) 13/12/13

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)

देहरादूनः दिनांकः 6 दिसम्बर, 2013

विषयः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–रा0प0का0/1219/लेखा–2/राज्यांश/2013–14 दिनांक 10.9.2013 तथा पत्र सं0 रा0प0का0/1427/लेखा–2/राज्यांश/2013–14 दिनांक 04.10.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत अतिरिक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष संलग्नक–01 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान–11 (सामान्य), अनुदान सँ0–30 (एस0सी0एस0पी0) एवं अनुदान सँ0 31(टी0एस0पी0) में सम्मिलित रूप से कुल धनराशि रू0 **06,74,83,000–00 (रूपये छः करोड़ चौहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र)** आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) वित्त विभाग के शासनादेश सँ0 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.3.2013 एवं शासनादेश सं0 413/ XXVII(1)/2013 दिनांक 10.6.2013 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति विषयक पत्र दिनांक 30.8.2013 (सामान्य, एस0सी0एस0पी0 व टी0एस0पी0) के क्रम में इस शर्त के साथ की जा रही है कि इस धनराशि का आहरण केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही किया जाय।

(3) निर्माण कार्यों के लिये अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय व भौतिक प्रगति भी शासन को प्रस्तुत की जाय।

(4) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(6) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(7) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

Exp CMC WHC / FC
11/12/13

AAO
A
13/12/13

(9) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(10) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02– इस सँम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 4202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

03– यह स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश सँ0 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.3.2013 एवं शासनादेश सं0 413/ XXVII(1)/2013 दिनांक 10.6.2013 में वर्णित शर्तों के अनुपालन में भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के दृष्टिगत राज्यांश के रूप में जारी की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

सँ0 1113 (i)/XXIV(1)/2013–16/2013 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
उप सचिव।

शासनादेश सं0–1113/XXIV(1)/2013-16/2013 दिनांक 06-12-13 का संलग्नक।

(धनराशि हजार रूपये में)

	लेखाशीर्षक	आय–व्ययक 2013–14 में कुल प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य) –आयोजनागत			
4202	शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारम्भिक शिक्षा		
04	सर्व शिक्षा अभियान		
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	78325	48048
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)–आयोजनागत			
4202	शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारम्भिक शिक्षा		
01	केन्द्रीय आयोजनागत		
0101	सर्व शिक्षा अभियान		
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	19327	17343
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)–आयोजनागत			
4202	शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारम्भिक शिक्षा		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें		
0101	सर्व शिक्षा अभियान		
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4069	2092
	कुल योग (अनुदान सँ0 11 + 30 + 31)	101721	67483

(रूपये छः करोड़ चौहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र)

(आर0 के0 तोमर)
उप सचिव

सं0 365 /XXIV(1)/2014–16/2013

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव ,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2014

विषयः **वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए सर्व शिक्षा योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–रा0प0का0/2652/लेखा–2/राज्यांश/2013–14 दिनांक 18.2.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें भारत सरकार के पत्र सं F.No. 10-5/2013-EE. 14 दिनांक 18.2.2014 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के दृष्टिगत राज्यांश की धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रू0 5215.36 लाख की धनराशि अवमुक्त होने के दृष्टिगत संलग्नक–01 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान–11 (सामान्य), अनुदान सॅ0 30(एस0सी0 एस0पी0) एवं अनुदान सॅ0 31(टी0एस0पी0) में कुल **रू0 2735.28 लाख (रूपये सत्ताईस करोड़ पैंतीस लाख अठाईस हजार मात्र)** की धनराशि (राज्यांश) आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) वित्त विभाग के शासनादेश सॅ0 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.3.2013 एवं शासनादेश सं0 413/ XXVII(1)/2013 दिनांक 10.6.2013 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

Fc
22.05.14

(8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा, 4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के वित्त विभाग के शासनादेश सँ0 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.3.2013 एवं शासनादेश सं0 413/ XXVII(1)/2013 दिनांक 10.6.2013 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में प्रशासकीय विभाग के स्तर से ही जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

सं0 (i)/XXIV(1)/2014–16/2013 टी0सी0 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

No.F.10-3/2014-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy
EE.14 Section
*****

(4)

New Delhi, dated 23rd May, 2014.

To

The Accounts Officer,
Pay and Accounts Office,
Department of School Education and Literacy,
Ministry of Human Resource Development,
Shastri Bhawan, New Delhi.

Sub:- Release of ad-hoc (first) installment of grants under SSA for the year 2014-15 to SSA, Uttarakhand

Sir,

I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs.22,63,53,000/- (Rupees Twenty Two crore Sixty Three lakh Fifty Three thousand only)** under **General Head for Schedule Caste Component** as ad-hoc (first) installment of grants for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV in Uttarakhand during the year 2014-15 to the SSA, Uttarakhand

2. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of implementation of the SSA and the Financial & Procurement Manual for SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

3. The amount sanctioned will be released to the State Government of Uttarakhand, who will disburse the entire funds through electronic transfer to **Account No. 1182101012885, Canara Bank, Anekant Palace,Rajpur Road, Dehradun,** Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun, Uttarakhand immediately but not later than 15 days.

4. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2015.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities approved by the Project Approval Board of Department of School Education and Literacy, Govt. of India as per the Annual Work Plan for the year 2014-15.

(iii) The State Implementation Society (SIS) shall keep the amounts sanctioned for SSA/KGBV under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(iv) The State Government shall release their corresponding share (35%) against the approved AWP&B 2014-2015 to SSA, Uttarakhand in the bank account maintained para 3 above with the month of receipt of central share.

(v) SSA, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(vi) The grantee (SIS) shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year.

(vii) An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved programme duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year.

Fz / KGBV
30.05.14

Humar

(मनजीत कुमार)
MANJEET KUMAR
अवर सचिव/Under Secretary
म.सं. वि. मन्त्रालय/Min. of H.R.D.
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
D/o School Education & Literacy
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(viii) The accounts and other records of the SSA Project Officer and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(ix) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme.

(x) No permanent posts shall be created under the SSA funds. Teacher posts shall be created by the State Government even where such posts are supported by SSA funding. Project positions for SSA implementation would be temporary, upto the duration of the project only.

(xiv) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if due has been transferred to the SSA, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure against central & state funds available with the SIS.

(xv) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xvi) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xvii) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

(xviii) The unspent balance of Central assistance released to State during the previous years will be adjusted while releasing the balance amount of first installment due to the State.

5. The expenditure will be debitable to Demand No. 59 - Department of School Education & Literacy, 3601 (Major Head) - General Education, 02 (Sub-Major Head) - Elementary Education, 789(Minor Head) - Sarva Shiksha Abhiyan, 04 (Sub Head) – Scheduled Caste Component, 01 - Sarva Shiksha Abhiyan (Amount to be met from GBS), 31 - Grant-in-aid General, 2014-15 (Plan).

6. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, D-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115. On receipt of the sanction letter, the Principal Accounts Officer may issue an advice to the Reserve Bank of India (Central Accounts Sanction), Dehradun for affording credit to the balance of the State Government. The Principal Accounts Officer may forward a copy of the advice to the Accountant General and Finance Department of the State Government along with a copy to undersigned in the Department of School Education & Literacy. State Government shall send intimation regarding receipt of grant-in-aid to Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115.

(MANJEET KUMAR)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No.
Ministry of H.R.D.
Department of School Education & Literacy
Govt. of India
New Delhi

7. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1734/2014/IFD dated 30.04.2014 and IF-II vide their Dy. No. 520/2014/IF-II dated 15.05.2014.

8. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

9. U.C. up to 2012-13 has been issued and hence no U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

Copy forwarded to:

1. State Project Director, Uttarakhand, Dehradun.
2. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Dehradun
3. The Secretary (Primary & Secondary Education), Government of Uttarakhand, Dehradun.
4. The Drawing and disbursing Officer (Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy in duplicate for drawal and disbursement electronically.
5. Office of the Director General of Audit-I Central Revenue OAD-II Section, AGCR Building I.P. Estate, New Delhi 110002.
6. The Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.
7. The Accountant General (A&E), Govt. of Uttarakhand, Dehradun.
8. IF-2 Section/E.C. Unit/IFD/EE-3 Section.
9. Guard File.

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

No.F.10-3/2014-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy
EE.14 Section
*****

New Delhi, dated 7th October, 2014.

To

The Accounts Officer,
Pay and Accounts Office,
Department of School Education and Literacy,
Ministry of Human Resource Development,
Shastri Bhawan, New Delhi.

Sub:- Release of balance of 1st installment of grants under SSA for the year 2014-15 to SSA, Uttarakhand.

Sir,

Project Approval Board (PAB), Government of India, in its 212th Meeting held on 24th May,2014 approved the Annual Work Plan and Budget 2014-15 for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV component of SSA in Uttarakhand State.

2. In continuation of this Ministry's sanction letter of even number dated 23.05.2014, I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs. 179,71,000/- (Rupees one crore seventy nine lakh seventy one thousand only)** under **General Head for Scheduled Tribe Component** as balance of 1st installment of grants for implementation of SSA, NPEGEL & KGBV in Uttarkhand during the year 2014-15 to the SSA, Uttarkhand. With this release, the total releases will be Rs.15880.57 lakh for the year 2014-15.

3. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of implementation of the SSA and the Financial & Procurement Manual for SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

4. The amount sanctioned will be released to the State Government of Uttarakhand, who will disburse the entire funds through electronic transfer to **Account No. 1182101012885, Canara Bank, Anekant Palace,Rajpur Road, Dehradun,** Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun, Uttarakhand immediately but not later than 15 days.

5. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2015.
(ii) It shall be utilized only for undertaking activities approved by the Project Approval Board of Department of School Education and Literacy, Govt. of India as per the Annual Work Plan for the year 2014-15.
(iii) The State Implementation Society (SIS) shall keep the amounts sanctioned for SSA/KGBV under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.
(iv) The State Government shall release their corresponding share (35%) against the approved AWP&B 2014-2015 to SSA, Uttarakhand in the bank account maintained para 3 above with the month of receipt of central share.
(v) SSA, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.
(vi) The grantee (SIS) shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year.
(vii) An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved programme duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year.

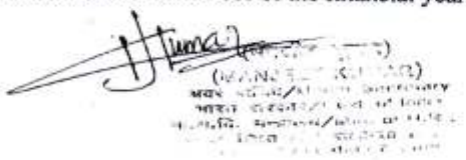

(viii) The accounts and other records of the SSA Project Officer and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(ix) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme.

(x) No permanent posts shall be created under the SSA funds. Teacher posts shall be created by the State Government even where such posts are supported by SSA funding. Project positions for SSA implementation would be temporary, upto the duration of the project only.

(xiv) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if due has been transferred to the SSA, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure against central & state funds available with the SIS.

(xv) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xvi) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xvii) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

(xviii) The unspent balance of Central assistance released to State during the previous years will be adjusted while releasing the balance amount of first installment due to the State.

6. The expenditure will be debitable to Demand No. 39 - Department of School Education & Literacy, 3601 (Major Head) – Grants-in-aid to State Govt., 02 (Sub-Major Head) – Grants for State Plan Scheme, 796 (Minor Head) - Scheduled Tribes sub Plan, 04 (Sub Head) – Sarva Shiksha Abhiyan, 02 - General Component (Amount to be met from PSK), 31 - Grant-in-aid General, 2014-15 (Plan).

7. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, D-Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115. On receipt of the sanction letter, the Principal Accounts Officer may issue an advice to the Reserve Bank of India (Central Accounts Sanction), Dehradun for affording credit to the balance of the State Government. The Principal Accounts Officer may forward a copy of the advice to the Accountant General and Finance Department of the State Government along with a copy to undersigned in the Department of School Education & Literacy. State Government shall send intimation regarding receipt of grant-in-aid to Principal Accounts Officer, Ministry of HRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115.

8. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 4745/2014/IFD dated 29.09.2014 and IF-II vide their Dy. No. 933/2014/IF-II dated 01.10.2014.

9. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

10. U.C. up to 2012-13 has been issued and hence no U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/09/2014–15 दिनांक: 8/ दिसम्बर, 2014

विषयः– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत अवमुक्त प्रथम किश्त के साथ राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1221/XXIV(1)/2014–11/2014 टी0सी0दिनांक 29 नवम्बर 2014 द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के दृष्टिगत राज्यांश की धनराशि को शामिल कर संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान स0–11 (सामान्य), अनुदान स0–30 (एस0सी0एस0पी0) व अनुदान स0–31 (टी0एस0पी0) में कुल धनराशि **रू0 90,48,47,000/–**(रूपये नब्बे करोड़ अड़तालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि (रू0 588150.00 हजार केन्द्रांश + 316697.00 हजार राज्यांश) अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार **रू0 90,48,47,000/–**(रूपये नब्बे करोड़ अड़तालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण कर चैक राज्य परियोजना निदेशक के नाम निर्गत करवाया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 व 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा, 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 17053-60 /5क(02)/09/2014–15 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन पटेलनगर, देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को इस आशय के साथ कि स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
6– उप शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सं0 122 /XXIV(1)/2014–11/2014 टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून : दिनाँक: 29 नवम्बर, 2014

विषयः **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत अवमुक्त प्रथम किस्त के साथ राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–रा0प0का0/1598/लेखा–2/केन्द्रांश–राज्यांश/2014–15 दिनांक 03.11..2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें भारत सरकार के पत्र सं0 F.No. 10-3/2014-EE.14 दिनांक 7.10.2014 द्वारा अनुदान सँ0 11, 30 एवं 31 में (सामान्य, एस0सी0पी0 व टी0एस0पी0) की प्रथम किस्त के अंश के रूप कुल रू0 265.47 लाख पूँजीगत मद में एवं भारत सरकार के पत्र सं0 F.No. 10-3/2014-EE.14 दिनांक 7.10.2014 द्वारा अनुदान सँ0 11, 30 एवं 31 (सामान्य एस0सी0पी0 व टी0एस0पी0) की प्रथम किस्त के अंश के रूप कुल रू0 5616.03 लाख सामान्य मद में अवमुक्त कुल केन्द्रांश रू0 5881.50 लाख तथा राज्यांश की धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रू0 5881.50 लाख (अनुदान सँ0 11, 30 एवं 31 में) की धनराशि अवमुक्त होने के दृष्टिगत संलग्नक–01 में उल्लिखित विवरणानुसार राज्यांश सहित अनुदान–11 (सामान्य), अनुदान सँ0 30(एस0सी0 एस0पी0) एवं अनुदान सँ0 31(टी0एस0पी0) में कुल **रू0 90,48,47,000.00(रूपये नब्बे करोड़ अड़तालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र)** की धनराशि (केन्द्रांश रू0 588150.00 हजार + राज्यांश रू0 316697.00 हजार) आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यो तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों तथा स्वीकृति में दी गयी शर्तो/प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सँ0 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.3.2014 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु पूँजीगत पक्ष के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपभोग करने से पूर्व नियमानुसार आंगणन की स्वीकृति सहित वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(6) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(7) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(8) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(9) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(10) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना, मानकों तथा शर्तो की अनुपालना भी सुनिश्चित की जाएगी।

02– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा, 4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सॅ0 318/XXVII(1)/2013 दिनांक 18–03–2014 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में प्रशासकीय विभाग के स्तर से ही जारी किया जा रहा है**संलग्नकः–यथोक्त।**

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0जोशी)
सचिव

सं0 **(i)/XXIV(1)/2014–11/2014 टी0सी0 तद्दिनाँक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबरॉय बिल्डिंग, देहरादून।

02. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनुसचिव।

शासनादेश सं0–1221 / XXIV(1)/2014-11/2014 TC दिनाँक29-11-14 संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक		आय–व्ययक 2014–15 में कुल प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2014–15
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)–आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
0104	सर्व शिक्षा अभियान(35 प्रतिशत राज्यांश)		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3015144	621825
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)–आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
0101	सर्व शिक्षा अभियान		
	20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	750490	214532
अनुदान संख्या–31 आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
0101	सर्व शिक्षा अभियान		
	20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	256300	27648
	योग	**4021934**	**864005**
अनुदान संख्या–11 आयोजनागत			
4202	शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारम्भिक शिक्षा		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
04	सर्व शिक्षा अभियान		
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	350000	29394
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0) आयोजनागत			
4202	शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		

01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारम्भिक शिक्षा		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
0101	सर्व शिक्षा अभियान		
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	140000	10142
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0) आयोजनागत			
4202	शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारम्भिक शिक्षा		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
0101	सर्व शिक्षा अभियान(35 प्रतिशत राज्यांश)		
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	8000	1306
	योग	**498000**	**40842**
	महायोग	**4519934**	**904847**

(रूपये नब्बे करोड़ अड़तालीस लाख सैतालीस हजार मात्र)

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
ननूरखेड़ा, देहरादून

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/ 09 /2014–15 दिनांक 27 जून 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 740/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 23 जून 2014 द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के दृष्टिगत राज्यांश की धनराशि को शामिल कर संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान स0–11 (सामान्य), अनुदान स0–30 (एस0सी0एस0पी0) व अनुदान स0–31 (टी0एस0पी0) में कुल धनराशि रू0 1,53,**83,18,000**/–(रूपये एक अरब तिरपन करोड़ तिरासी लाख अठारह हजार मात्र) की धनराशि (रू0 9999.07 लाख केन्द्रांश + 5384.11 लाख राज्यांश) अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 1,53,**83,18,000**/–(रूपये एक अरब तिरपन करोड़ तिरासी लाख अठारह हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण कर चैक राज्य परियोजना निदेशक के नाम निर्गत करवाया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 व 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा, 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 5933-39 /5क(02)/09 /2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को इस आशय के साथ कि स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
6– उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

27/6/14
(पी0के0 जोशी)

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Secondery Education (S043)

आवंटन पत्र संख्या - 740/XXIV(1)/2014-11/2014 t.c DATED 23-06-2014

अलोटमेंट आई डी - S1406300200

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक -26-Jun-2014

HOD Name - Director Elementary Education (4514)

लेखा शीर्षक

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत पर

201 - प्रारम्भिक शिक्षा

01 - सर्व शिक्षा अभि यान (35% राज्याँश)

01 - सामान्य शिक्षा

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	0	33729000	33729000
	0	**33729000**	**33729000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 33729000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Secondery Education (S043)

आवंटन पत्र संख्या - 740/XXIV(1)/2014-11/2014 t.c DATED 23-06-2014

अलोटमेंट आई डी - S1406310201

अनुदान संख्या - 031

आवंटन पत्र दिनांक -26-Jun-2014

HOD Name - Director Elementary Education (4514)

लेखा शीर्षक

4202 - शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

201 - प्रारम्भिक शिक्षा

01 - सर्व शि क्षा अभि यान (35% राज्याँश)

01 - सामान्य शिक्षा

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	0	4346000	4346000
	0	**4346000**	**4346000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 4346000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Secondery Education (S043)

आवंटन पत्र संख्या - 740/XXIV(1)/2014-11/2014 T.C Dated-23-06-14

अलोटमेंट आई डी - S1406110199

अनुदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक -26-Jun-2014

HOD Name - Director Elementary Education (4514)

लेखा शीर्षक

4202 - शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

201 - प्रारम्भिक शिक्षा

00 - सर्वशिक्षा अभियान

01 - सामान्य शिक्षा

04 - सर्वशिक्षा अभियान

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	0	97765000	97765000
	0	**97765000**	**97765000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 97765000

No. F. 10-5/2011-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy

New-Delhi, the 24th May, 2011

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan
New Delhi

Subject:- Release of ad-hoc grants under SSA for the year 2011-12 (Plan) to SSA, Uttarakhand.

Sir,

I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs. 1,24,24,000/- (Rupees one crore twenty four lakh twenty four thousand only)** under **Grants-in-aid for creation of capital assets head** as ad-hoc grants for implementation of SSA during the year 2011-12 to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun and these grants will be adjusted at the time of release of Ist installment of Central share for the year 2011-12. With this release, the total releases will be Rs.10387.89 lakh as ad-hoc grants for the year 2011-12.

2. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

3. The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

4. The State will maintain separate accounts for grants released under Grant-in-aid General and Grants for creation of Capital Assets. Further at the end of the financial year State will provide expenditure and unspent balance on General and Capital object head separately.

5. The amount sanctioned will be drawn by the Drawing and Disbursing Officer(Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Government of India New Delhi on a grant-in-aid bill and disbursed to the grantee through electronic/telegraphic transfer of fund to the State Project Director, Uttarkhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand during the current financial year 2011-12. The details of bank account of the society is as follow:

F.C/ARO
08.06.11

Account No. 1182101012885
Canara Bank, Anekant Palace
Rajpur Road, Dehrudun

6. Authorisation letter received from the payee is enclosed for making the e-payment in favour of Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

7. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2012 and shall be utilized within a reasonable period from the date of drawl.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities proposed in the Work Plan for the year 2011-2012 and as approved by the Project Approval Board, and by the Government of India on the basis norms of expenditure.

(iii) The assets, if any, acquired wholly or substantially out of this grant, should not, without the prior sanction of the Government of India, be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant has been sanctioned.

(iv) The grantee shall maintain a separate and proper account of the expenditure incurred out of the grant and the accounts so maintained shall be open to audit by the Comptroller & Auditor General of India or any authority deputed by him for the purpose as per rules.

(v) The State Implementation Society shall keep the amounts sanctioned for SSA/NPEGEL under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(vi) The State Government shall release their correspondence share (35%) against AWP&B 2011-2012 to Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand in time as per stipulation mentioned in the Framework of the scheme besides releasing the entire accumulated deficit of State share since 2000-2001. Subsequent installment of grant would be sanctioned only after the entire backlog of State share including the one due against the current year approved budget is released by the State Government to the State Society.

(vii) Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(viii) The amount sanctioned for a district shall be made available to the district level institution authorized for the implementation of SSA. Individual districts shall spend the amount given to them on the items proposed by them in the District Plans for the year 2011-2012 and as approved by the PAB, and in accordance with other general principles and Framework of the scheme and the terms of this sanction.

(ix) The grant shall be utilized only for undertaking activities as approved by the Government of India on the basis of norms of expenditure.

(x) State Mission Authority of Education for All, Uttarakhand shall fully implement the Official Language Policy of the Union Government i.e. It shall full comply with Official Language Act, 1963 and Office Language (used for the official purpose of the Union) Rules, 1976 etc.

(xi) The grantee shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year. An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved project duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year. The unspent balance, if any shall be taken into account before funds or subsequent years are released.

(xii) A register of assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be acquired should be sent to this Ministry not later than one month from the close of the financial year. Such copies should continue to be furnished even after Government grant ceased. The Statements shall relate to all assets created wholly or substantially out of the Governmental grant upto the end of the period to which the return relates.

(xiii) The accounts and other records of the Project Officers and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(xiv) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme and reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(xv) There shall be no appointment of permanent staff, except additional teachers only as per SSA norms. The existing staff of the State Government should be optimally utilized. The principal work of project implementation shall be on the mainstream administrative establishment at State and district levels. However, in case there is any need to appoint contractual staff for a limited period for the performance of specialised jobs for which expertise is not available with them. Such contractual staff may only be hired by the district/block/village levels only and the cost maintained within 6% management cost as envisaged under the scheme.

(xvi) The guidelines issued by the Government of India from time to time regarding monitoring management and financial control and other procedure would be followed in the execution of the Project.

(xvii) The State Government should give a written commitment for meeting its share of the SSA/NPEGEL outlay.

(xviii) First installment of the State share should also be released to the Society within one month of the release of central share to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

(xix) Teachers appointed against posts created through SSA funds should be made accountable to the VEC for at least salary payment. The latter would monitor the attendance before releasing the salary.

(xx) VECs or equivalent bodies should be constituted and accounts opened to incur expenditure under teachers grant, civil works, maintenance grants, school grants and other such expenditure which has to be incurred only through these bodies as per SSA norms and should be utilized within one month of its release.

(xxi) State Government will maintain their level of investment in elementary education as in 1999-2000 and give the details of this to Government of India before the release of installment. The contribution as State share for SSA will be over and above this investment.

(xxii) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if any, has been transferred to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure as far as money already released is concerned.

.../..

D.
Literacy
Dte ... New Delhi

(xxiii) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render toe grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xxiv) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xxv) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

8. The expenditure will be debitable to Demand No. 58 Department of School Education and Literacy; Major Head 2202; General Education –01-Elementary Education -796-Scheduled Tribe sub plans - 03- Sarva Shiksha Abhiyan - 03.01 General Component (GBS) - 03.01.35 Grant-in-aid for creation of capital assets 2011-12 (Plan).

9. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1620/11/IFD dated 26.04.2011and IF-II vide their Dy. No. 731/2011/IF-II dated 18.05.2011.

10. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

11. No U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(A. K. Tewari)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23384582

(A. K. Tewari)
Secretary
D/o School Education & Literacy
New Delhi

Copy forwarded to:

1. State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand 'The grantee institution is required to submit the under mentioned documents as per terms and conditions of the sanction letter to enable the Ministry to release the grant:-

   (a) Bond for **Rs. 10387.89 lakh** in revised format.
   (b) Authorisation letter as in the revised format.

2. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand , Dehradun.

3. The Principal Secretary (Education), Government of Uttarakhand, Sachicalaya, Dehradun-248001, Uttarakahnd. The State Government is requested to kindly furnish written commitment as per para 6 (vi) of the sanction.

4. The Drawing and disbursing Officer (Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy in duplicate for drawal and disbursement electronically.

5. Office of the Director General of Audit-I Central Revenue OAD-II Section, AGCR Building I.P. Estate, New Delhi 110002.

6. The Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.

7. The Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.

8. IF-2 Section/E.C. Unit/IFD/EE-15 section.

9. Shri Shailander Sharma, Chief Consultant TSG Ed-CIL New Delhi.

10. Guard File.

(A. K. Tewari)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23384582

प्रेषक,

बजट आवंटन पत्र

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग देहरादून।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद
ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग. देहरादून।

पत्रांक–अर्थ–2/ 123-30 /5क(01)03/2011–12 दिनांक 19 नवम्बर 2011

विषयः– मध्याह्न भोजन योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में अवशेष धनराशिकी स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1104/XXIV(1)/2011–29/2011 दिनांक 15 नवम्बर 2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में सर्व शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल ₹ 1136243000/– (रुपये एक अरब तेरह करोड़ बासठ लाख तेताल़ीस हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा निम्नांकित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(1) आय–व्ययक में बजट प्राविधान के सापेक्ष वर्तमान में व्यय हेतु निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि (सर्व शिक्षा के अर्न्तगत मात्र राज्यांश तथा मध्याह्न भोजन योजना में केन्द्रांश व राज्यांश सहित) के सापेक्ष उक्त योजनाओं में भारत सरकार से अद्यावधिक प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अपेक्षित राज्यांश की सीमा तक ही (जो योजनान्तर्गत स्वीकृत परिव्यय की सीमा में हो) धनराशि आहरण/व्यय किया जायेगा। शेष धनराशि भारत सरकार से अग्रेत्तर केन्द्रांश प्राप्त होने पर योजनान्तर्गत वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सर्व शिक्षा अभियान में मात्र राज्यांश तथा मध्याह्न भोजन योजना में केन्द्रांश व राज्यांश सहित धनराशि आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हों।

(3) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय तथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारणी बनाकर किया जाय।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय कदापि न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन/निदेशालय को

क्रमश ::2::

Budget 11-12
16

अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवर शासन/निदेशालय को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्याः 1 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखि सम्बन्धित ब्यौरवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा बजट की अंकना केन्द्रीय बज पंजिका (बेसिक) के पृष्ठ–2, 16, 18, 19, 21 एवं 22 पर की गयी है।

संलग्नक–शासनादेश।

भवदीय,

19/11/2011

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: अर्थ–2/ /5क(01)03/2011–12 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– सचिव शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
5– उप शिक्षा निदेशक, नियोजन/निदेशालय अधिष्ठान शिक्षा निदेशालय।
6– आहरण वितरण अधिकारी शिक्षा निदेशालय।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पत्रांक: अर्थ–2/123-30 /5क(01)03/2011–12 दिनांक 19 नवम्बर 2011 का संलग्नक

	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	गत आवंटन	वर्तमान आंवटन	कुल आवंटन
	अनुदान संख्या 11		धनराशि हजार रुपये में		
2202–	सामान्य शिक्षा				
01–	प्रारम्भिक शिक्षा				
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय				
01–	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें				
0102–	विद्यालयों में पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना				
20	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1142317	426673	369197	795870
800–	अन्य व्यय				
01–	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें				
0104–	सर्व शिक्षा अभियान (35प्रति0 राज्यांश)				
20–	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1007654	286201	231445	517646
4202–	शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय				
01–	सामान्य शिक्षा				
201–	प्रारम्भिक शिक्षा				
04–	सर्व शिक्षा अभियान				
35–	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	720000	0	335390	335390
	योग अनुदान संख्या 11		**712874**	**936032**	**1648906**
	अनुदान सं0 30				
2202–	सामान्य शिक्षा				
01–	प्रारम्भिक शिक्षा				
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय				
01–	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना				
0101–	विद्यालयों में पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना				
20	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	336594	124515	91101	215616
800–	अन्य व्यय				
01–	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें				
0101–	सर्व शिक्षा अभियान (35प्रति0 राज्यांश)				
20–	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	393642	196821	84473	281294
	योग अनुदान संख्या 30		**321336**	**175574**	**496910**
	अनुदान सं0 31				
2202–	सामान्य शिक्षा				
01–	प्रारम्भिक शिक्षा				
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय				
01–	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें				
0101–	विद्यालयों में पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना				
20	सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	56098	20506	19179	39685
800–	अन्य व्यय				
01–	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें				
0101–	सर्व शिक्षा अभियान				
20–	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	54000	27000	5458	32458
	योग अनुदान संख्या 31		**47506**	**24637**	**72143**
	सम्पूर्ण योग अनुदान संख्या 11+30+31		**1081716**	**1136243**	**2217959**

(रुपये एक अरब तेरह करोड़ बासठ लाख तेतालीस हजार मात्र)

Budget 11-12
18

19/11/2011
(पी0के0 जोशी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा निदेशालय।

सख्या–1104/XXIV(1)/2011–29/2011

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 15 नवम्बर, 2011

विषयः– **मध्यान्ह भोजन योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–2012 में अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, ननूरखेड़ा देहरादून के पत्र संख्या–1575/लेखा–2/राज्यांश/2011–12, दिनांक 09.09.2011 एवं पत्र संख्या–241/एमबीएम–08/2011–12, दिनांक 14.09.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में बेसिक शिक्षा विभाग के आयोजनागत पक्ष की मध्यान्ह भोजन योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत पर व्यय हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या–11(राजस्व एवं पूंजीगत), 30 एवं 31 में कुल रू0 11362.43 लाख (रूपये एक अरब तेरह करोड़ बासठ लाख तिरालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) आय–व्ययक में बजट प्राविधान के सापेक्ष वर्तमान में व्यय हेतु निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि (सर्व शिक्षा के अन्तर्गत मात्र राज्यांश तथा मध्यान्ह भोजन योजना में केन्द्रांश व राज्यांश सहित) के सापेक्ष उक्त योजनाओं में भारत सरकार से अद्यावधिक प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अपेक्षित राज्यांश की सीमा तक ही (जो योजनान्तर्गत स्वीकृत परिव्यय की सीमा में हो) धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा। शेष धनराशि भारत सरकार से अग्रेत्तर केन्द्रांश प्राप्त होने पर ही योजनान्तर्गत वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सर्व शिक्षा अभियान में मात्र राज्यांश तथा मध्यान्ह भोजन योजना में केन्द्रांश व राज्यांश सहित धनराशि आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों का विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों की विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये। उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2. यह स्वीकृति पूर्व में शासनादेश संख्या–837/XXIV(1)/2011–29 /2011, दिनांक 21.07.2011 में स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त है।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–238(P)/XXVII (3)/2011–12, दिनांक 11.11.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्, ननूरखेड़ा देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से)।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

संख्या–1104/XXIV(1)/2011–29/2011, दिनांक 15/11/2011 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक		स्वीकृत धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)		
2202–	सामान्य शिक्षा	
01–	प्रारम्भिक शिक्षा	
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	
01–	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं	
0102–	विद्यालयों में पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना	
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3691.97
800–	अन्य व्यय	
01–	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं	
0104–	सर्व शिक्षा अभियान (35 % राज्यांश)	2314.45
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	
4202–	शिक्षा खेलकूल पर पूंजीगत परिव्यय	
01–	सामान्य शिक्षा	
201–	प्रारम्भिक शिक्षा	
04–	सर्व शिक्षा अभियान	
	35–पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान	3353.90
	योग (अनुदान संख्या–11)–	9360.32
अनुदान संख्या–30 (एस.सी.एस.पी.)		
0101–	विद्यालयों में पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना	
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	911.01
0101–	सर्व शिक्षा अभियान (35 % राज्यांश)	
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	844.73
	योग (अनुदान संख्या–30)–	1755.74
अनुदान संख्या–31 (टी.एस.पी.)		
0101–	विद्यालयों में पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना	
20–	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	191.79
0101–	सर्व शिक्षा अभियान	
20–	सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	54.58
	योग (अनुदान संख्या–31)–	246.37
	कुल योग (अनुदान संख्या–11+30+31)–	11362.43

(रूपये एक अरब तेरह करोड़ बासठ लाख तैतालीस हजार मात्र)

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

कार्यालय
डाक प्राप्ति 517
दिनांक .....
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद

No. F. 10-5/2011-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy

New Delhi, the 24th May, 2011

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan
New Delhi

Subject:- Release of ad-hoc grants under SSA for the year 2011-12 (Plan) to SSA, Uttarakhand.

Sir,

I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs. 10,70,78,000/- (Rupees ten crore seventy lakh seventy eight thousand only)** under **Grants-in-aid for creation of capital assets head** as ad-hoc grants for implementation of SSA during the year 2011-12 to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun and these grants will be adjusted at the time of release of Ist installment of Central share for the year 2011-12. With this release, the total releases will be Rs.10387.89 lakh as ad-hoc grants for the year 2011-12.

2. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

3. The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

4. The State will maintain separate accounts for grants released under Grant-in-aid General and Grants for creation of Capital Assets. Further at the end of the financial year State will provide expenditure and unspent balance on General and Capital object head separately.

5. The amount sanctioned will be drawn by the Drawing and Disbursing Officer(Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Government of India New Delhi on a grant-in-aid bill and disbursed to the grantee through electronic/telegraphic transfer of fund to the State Project Director, Uttarkhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand during the current financial year 2011-12. The details of bank account of the society is as follow:

Account No. 1182101012885
Canara Bank, Anekant Palace
Rajpur Road, Dehrudun

F.C. MAPO
08.06.11

Dir... Sch. Edn. & Literacy
...Delhi/New Delhi

.../..

6. Authorisation letter received from the payee is enclosed for making the e-payment in favour of Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

7. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2012 and shall be utilized within a reasonable period from the date of drawl.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities proposed in the Work Plan for the year 2011-2012 and as approved by the Project Approval Board, and by the Government of India on the basis norms of expenditure.

(iii) The assets, if any, acquired wholly or substantially out of this grant, should not, without the prior sanction of the Government of India, be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant has been sanctioned.

(iv) The grantee shall maintain a separate and proper account of the expenditure incurred out of the grant and the accounts so maintained shall be open to audit by the Comptroller & Auditor General of India or any authority deputed by him for the purpose as per rules.

(v) The State Implementation Society shall keep the amounts sanctioned for SSA/NPEGEL under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(vi) The State Government shall release their correspondence share (35%) against AWP&B 2011-2012 to Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand in time as per stipulation mentioned in the Framework of the scheme besides releasing the entire accumulated deficit of State share since 2000-2001. Subsequent installment of grant would be sanctioned only after the entire backlog of State share including the one due against the current year approved budget is released by the State Government to the State Society.

(vii) Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(viii) The amount sanctioned for a district shall be made available to the district level institution authorized for the implementation of SSA. Individual districts shall spend the amount given to them on the items proposed by them in the District Plans for the year 2011-2012 and as approved by the PAB, and in accordance with other general principles and Framework of the scheme and the terms of this sanction.

(ix) The grant shall be utilized only for undertaking activities as approved by the Government of India on the basis of norms of expenditure.

(x) State Mission Authority of Education for All, Uttarakhand shall fully implement the Official Language Policy of the Union Government i.e. It shall full comply with Official Language Act, 1963 and Office Language (used for the official purpose of the Union) Rules, 1976 etc.

(xi) The grantee shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year. An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved project duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year. The unspent balance, if any shall be taken into account before funds or subsequent years are released.

(xii) A register of assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be acquired should be sent to this Ministry not later than one month from the close of the financial year. Such copies should continue to be furnished even after Government grant ceased. The Statements shall relate to all assets created wholly or substantially out of the Governmental grant upto the end of the period to which the return relates.

(xiii) The accounts and other records of the Project Officers and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(xiv) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme and reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(xv) There shall be no appointment of permanent staff, except additional teachers only as per SSA norms. The existing staff of the State Government should be optimally utilized. The principal work of project implementation shall be on the mainstream administrative establishment at State and district levels. However, in case there is any need to appoint contractual staff for a limited period for the performance of specialised jobs for which expertise is not available with them. Such contractual staff may only be hired by the district/block/village levels only and the cost maintained within 6% management cost as envisaged under the scheme.

(xvi) The guidelines issued by the Government of India from time to time regarding monitoring management and financial control and other procedure would be followed in the execution of the Project.

(xvii) The State Government should give a written commitment for meeting its share of the SSA/NPEGEL outlay.

(xviii) First installment of the State share should also be released to the Society within one month of the release of central share to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

(xix) Teachers appointed against posts created through SSA funds should be made accountable to the VEC for at least salary payment. The latter would monitor the attendance before releasing the salary.

(xx) VECs or equivalent bodies should be constituted and accounts opened to incur expenditure under teachers grant, civil works, maintenance grants, school grants and other such expenditure which has to be incurred only through these bodies as per SSA norms and should be utilized within one month of its release.

(xxi) State Government will maintain their level of investment in elementary education as in 1999-2000 and give the details of this to Government of India before the release of installment. The contribution as State share for SSA will be over and above this investment.

(xxii) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if any, has been transferred to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure as far as money already released is concerned.

(xxiii) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

.../..

(xxiv) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xxv) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

8. The expenditure will be debitable to Demand No. 58 Department of School Education and Literacy; Major Head 2202; General Education –01-Elementary Education -789- Special Component Plan for Scheduled Caste - 02- Sarva Shiksha Abhiyan - 02.01 General Component (GBS) - 02.01.35 Grant-in-aid for creation of capital assets 2011-12 (Plan).

9. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1670/11/IFD dated 26.04.2011and IF-II vide their Dy. No. 731/2011/IF-II dated 18.05.2011.

10. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

11. No U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(A. K. Tewari)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23384582

(A. K. Tewari)
Under Secretary
D/o School Education & Literacy
New Delhi

Copy forwarded to:

1. State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand The grantee institution is required to submit the under mentioned documents as per terms and conditions of the sanction letter to enable the Ministry to release the grant:-

   (a) Bond for **Rs.10387.89 lakh** in revised format.
   (b) Authorisation letter as in the revised format.

2. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand , Dehradun.

3. The Principal Secretary (Education), Government of Uttarakhand, Sachicalaya, Dehradun-248001, Uttarakahnd. The State Government is requested to kindly furnish written commitment as per para 6 (vi) of the sanction.

4. The Drawing and disbursing Officer (Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy in duplicate for drawal and disbursement electronically.

5. Office of the Director General of Audit-I Central Revenue OAD-II Section, AGCR Building I.P. Estate, New Delhi 110002.

6. The Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.

7. The Accountant General, Uttarakhand, Dehradun

8. IF-2 Section/E.C. Unit/IFD/EE-15 section.

9. Shri Shailander Sharma, Chief Consultant TSG Ed-CIL New Delhi.

10. Guard File.

(A. K. Tewari)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23384582

No. F. 10-5/2011-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy

New Delhi, the 24th May, 2011

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan
New Delhi

Subject:- Release of ad-hoc grants under SSA for the year 2011-12 (Plan) to SSA, Uttarakhand.

Sir,

I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs. 29,60,13,000/- (Rupees twenty nine crore sixty lakh thirteen thousand only)** under **Grants-in-aid for creation of capital assets head** as ad-hoc grants for implementation of SSA during the year 2011-12 to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun and these grants will be adjusted at the time of release of Ist installment of Central share for the year 2011-12. With this release, the total releases will be Rs.10387.89 lakh as ad-hoc grants for the year 2011-12.

2. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

3. The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

4. The State will maintain separate accounts for grants released under Grant-in-aid General and Grants for creation of Capital Assets. Further at the end of the financial year State will provide expenditure and unspent balance on General and Capital object head separately.

5. The amount sanctioned will be drawn by the Drawing and Disbursing Officer(Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Government of India New Delhi on a grant-in-aid bill and disbursed to the grantee through electronic/telegraphic transfer of fund to the State Project Director, Uttarkhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand during the current financial year 2011-12. The details of bank account of the society is as follow:

Account No. 1182101012885
Canara Bank, Anekant Palace
Rajpur Road, Dehrudun

6. Authorisation letter received from the payee is enclosed for making the e-payment in favour of Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

7. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2012 and shall be utilized within a reasonable period from the date of drawl.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities proposed in the Work Plan for the year 2011-2012 and as approved by the Project Approval Board, and by the Government of India on the basis norms of expenditure.

(iii) The assets, if any, acquired wholly or substantially out of this grant, should not, without the prior sanction of the Government of India, be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant has been sanctioned.

(iv) The grantee shall maintain a separate and proper account of the expenditure incurred out of the grant and the accounts so maintained shall be open to audit by the Comptroller & Auditor General of India or any authority deputed by him for the purpose as per rules.

(v) The State Implementation Society shall keep the amounts sanctioned for SSA/NPEGEL under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(vi) The State Government shall release their correspondence share (35%) against AWP&B 2011-2012 to Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand in time as per stipulation mentioned in the Framework of the scheme besides releasing the entire accumulated deficit of State share since 2000-2001. Subsequent installment of grant would be sanctioned only after the entire backlog of State share including the one due against the current year approved budget is released by the State Government to the State Society.

(vii) Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(viii) The amount sanctioned for a district shall be made available to the district level institution authorized for the implementation of SSA. Individual districts shall spend the amount given to them on the items proposed by them in the District Plans for the year 2011-2012 and as approved by the PAB, and in accordance with other general principles and Framework of the scheme and the terms of this sanction.

(ix) The grant shall be utilized only for undertaking activities as approved by the Government of India on the basis of norms of expenditure.

(x) State Mission Authority of Education for All, Uttarakhand shall fully implement the Official Language Policy of the Union Government i.e. It shall full comply with Official Language Act, 1963 and Office Language (used for the official purpose of the Union) Rules, 1976 etc.

(xi) The grantee shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year. An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved project duly signed by a Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year. The unspent balance, if any shall be taken into account before funds or subsequent years are released.

(A. K. TEWARI)
Secretary
of H. R. D.

.../..

(xii) A register of assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be acquired should be sent to this Ministry not later than one month from the close of the financial year. Such copies should continue to be furnished even after Government grant ceased. The Statements shall relate to all assets created wholly or substantially out of the Governmental grant upto the end of the period to which the return relates.

(xiii) The accounts and other records of the Project Officers and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(xiv) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme and reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(xv) There shall be no appointment of permanent staff, except additional teachers only as per SSA norms. The existing staff of the State Government should be optimally utilized. The principal work of project implementation shall be on the mainstream administrative establishment at State and district levels. However, in case there is any need to appoint contractual staff for a limited period for the performance of specialised jobs for which expertise is not available with them. Such contractual staff may only be hired by the district/block/village levels only and the cost maintained within 6% management cost as envisaged under the scheme.

(xvi) The guidelines issued by the Government of India from time to time regarding monitoring management and financial control and other procedure would be followed in the execution of the Project.

(xvii) The State Government should give a written commitment for meeting its share of the SSA/NPEGEL outlay.

(xviii) First installment of the State share should also be released to the Society within one month of the release of central share to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

(xix) Teachers appointed against posts created through SSA funds should be made accountable to the VEC for at least salary payment. The latter would monitor the attendance before releasing the salary.

(xx) VECs or equivalent bodies should be constituted and accounts opened to incur expenditure under teachers grant, civil works, maintenance grants, school grants and other such expenditure which has to be incurred only through these bodies as per SSA norms and should be utilized within one month of its release.

(xxi) State Government will maintain their level of investment in elementary education as in 1999-2000 and give the details of this to Government of India before the release of installment. The contribution as State share for SSA will be over and above this investment.

(xxii) The next installment, if due, would only released after the previous installment of State share, if any, has been transferred to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand and substantial progress has been made in expenditure as far as money already released is concerned.

(xxiii) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render toe grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(... TEWARI)
... Secretary
... of H. R. D.
... Literacy

.../..

108 83

(xxiv) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Office of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xxv) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

8. The expenditure will be debitable to Demand No. 58 Department of School Education and Literacy; Major Head 2202; General Education –01-Elementary Education -111- Sarva Shiksha Abhiyan - 01-General Component- 01.02 Sarva Shiksha Abhiyan (PSK) - 01.02.35 Grant-in-aid for creation of capital assets 2011-12 (Plan).

9. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 1620/11/IFD dated 26.04.2011and IF-II vide their Dy. No. 731/2011/IF-II dated 18.05.2011.

10. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

11. No U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(A. K. Tewari)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23384582

(A. K. TEWARI)
Under Secretary
Govt. of H. R. D.
D/o School Education & Literacy
New Delhi

Copy forwarded to:

1. State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand The grantee institution is required to submit the under mentioned documents as per terms and conditions of the sanction letter to enable the Ministry to release the grant:-

   (a) Bond for **Rs. 10387.89 lakh** in revised format.
   (b) Authorisation letter as in the revised format.

2. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand , Dehradun.

3. The Principal Secretary (Education), Government of Uttarakhand, Sachicalaya, Dehradun-248001, Uttarakahnd. The State Government is requested to kindly furnish written commitment as per para 6 (vi) of the sanction.

4. The Drawing and disbursing Officer (Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy in duplicate for drawal and disbursement electronically.

5. Office of the Director General of Audit-I Central Revenue OAD-II Section, AGCR Building I.P. Estate, New Delhi 110002.

6. The Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.

7. The Accountant General, Uttarakhand, Dehradun

8. IF-2 Section/E.C. Unit/IFD/EE-15 section.

9. Shri Shailander Sharma, Chief Consultant TSG Ed-CIL New Delhi.

10. Guard File.

A.K. Tewari

(A. K. Tewari)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23384582

(A. K. Tewari)
Under Secretary
Govt. of India, M. H. R. D.
Department of School Education & Literacy
D/o SE&L/New Delhi

Progress of Toilet near River Ganga 2016-17 (Swachchh Bharat Kosh)

District	Block	School Code	School Name	Progress	Amount in Lack
Rudraprayag	Agastyamuni	5030124601	PS Sari	complete	2.14
Rudraprayag	Agastyamuni	5030124401	PS Chamsil	plasater	2.14
Rudraprayag	Agastyamuni	5030124901	PS Jhalimath	complete	2.14
Rudraprayag	Agastyamuni	5030124701	PS Chinka	plaster	2.14
Rudraprayag	Agastyamuni	5030124702	UPS Chinka	plaster	2.14
Rudraprayag	Agastyamuni	5030108001	PS Chandrapuri	plaster	2.14
Rudraprayag	Agastyamuni	5030107701	PS Hat	door bend	2.14
Rudraprayag	Agastyamuni	5030127501	PS Geed Bhuter	complete	2.14
Rudraprayag	Ukhimath	5030303001	PS Poldi	complete	2.14
Total					19.26

AE (SSA)

No. F. 10-5/2012-EE.14
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education and Literacy

New Delhi, the 11th July, 2012

To

The Pay and Account Officer,
Pay and Account Office,
Department of School Education and Literacy
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhavan
New Delhi

Subject:- Release of 2nd trench of 1st installment of Central share under SSA for the year 2012-13 (Plan) to SSA, Uttarakhand.

Sir,

In continuation of this Department's sanction letter of even number dated 11.05.2012, I am directed to convey the sanction of the president to release of **Rs.11,79,02,000/- (Rupees eleven crore seventy nine lakh two thousand only)** under **Grants-in-aid General Head** as 2nd trench of 1st installment of Central share for implementation of SSA, NPEGEL, KGBV relating to child entitlements like textbooks, uniform, school grants, etc. within the ceiling of PAB approved outlay for 2012-13 to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun. With this release, the total releases will be Rs.8889.10 lakh for the year 2012-13.

2. The sanction has been accorded subject to the terms and conditions contained in the Framework of SSA issued by this Ministry and to the adherence of financial, administrative and policy norms stipulated therein.

3. The pattern of grant/expenditure has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme as approved by the Ministry of Finance.

4. The State will maintain separate accounts for grants released under Grant-in-aid General and Grants for creation of Capital Assets. Further at the end of the financial year State will provide expenditure and unspent balance on General and Capital object head separately.

5. The amount sanctioned will be drawn by the Drawing and Disbursing Officer(Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Government of India New Delhi on a grant-in-aid bill and disbursed to the grantee through electronic/telegraphic transfer of fund to the State Project Director, Uttarkhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun, Uttarakhand during the current financial year 2012-13. The details of bank account of the society is as follow:

Account No. 1182101012885
Canara Bank, Anekant Palace
Rajpur Road, Dehrudun

6. Authorisation letter received from the payee is enclosed for making the e-payment in favour of Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

7. **The grant shall be subject to the following conditions:**

(i) It shall be drawn during the current financial year before March 31, 2013 and shall be utilized within a reasonable period from the date of drawl.

(ii) It shall be utilized only for undertaking activities proposed in the Work Plan for the year 2012-13 and as approved by the Project Approval Board, and by the Government of India on the basis norms of expenditure.

(iii) The assets, if any, acquired wholly or substantially out of this grant, should not, without the prior sanction of the Government of India, be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant has been sanctioned.

(iv) The grantee shall maintain a separate and proper account of the expenditure incurred out of the grant and the accounts so maintained shall be open to audit by the Comptroller & Auditor General of India or any authority deputed by him for the purpose as per rules.

(v) The State Implementation Society shall keep the amounts sanctioned for SSA/NPEGEL under a separate Bank Account and maintain separate account for its disbursement and expenditure as per rules.

(vi) The State Government shall release their correspondence share (35%) against AWP&B 2012-13 to Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand in time as per stipulation mentioned in the Framework of the scheme besides releasing the entire accumulated deficit of State share since 2000-2001. Subsequent installment of grant would be sanctioned only after the entire backlog of State share including the one due against the current year approved budget is released by the State Government to the State Society.

(vii) Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand shall disburse the amount to the districts immediately on receipt of the grant from Central and State Government to ensure smooth implementation of the programme.

(viii) The amount sanctioned for a district shall be made available to the district level institution authorised for the implementation of SSA. Individual districts shall spend the amount given to them on the items proposed by them in the District Plans for the year 2012-13 as approved by the PAB, and in accordance with other general principles and framework of the scheme and the terms of this sanction.

(ix) The grant shall be utilized only for undertaking activities as approved by the Government on the basis of norms of expenditure.

(x) State Mission Authority of Education for All, Uttarakhand shall fully implement the Official Language Policy of the Union Government i.e. It shall full comply with Official Language Act, 1963 and Office Language (used for the official purpose of the Union) Rules, 1976 etc.

(xi) The grantee shall furnish this Department with item-wise statement of expenditure on a quarterly basis and other reports on physical and financial progress in approved formats. The grantee will also submit annual progress report of the project within one month from the close of the financial year. An annual statement of accounts along with a certificate of utilization of the grant for the approved project duly signed by a

Chartered Accountant and the authorized signatory of the Project-In-charge in the State will be submitted within nine months from close of the financial year. The unspent balance, if any shall be taken into account before funds or subsequent years are released.

(xii) A register of assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be acquired should be sent to this Ministry not later than one month from the close of the financial year. Such copies should continue to be furnished even after Government grant ceased. The Statements shall relate to all assets created wholly or substantially out of the Governmental grant upto the end of the period to which the return relates.

(xiii) The accounts and other records of the Project Officers and Implementation Institutions shall be open to inspection by an Officer of the Ministry of Human Resource Development or any person deputed by the Ministry for the purpose.

(xiv) The grantee shall follow strictly all the instructions issued by the Government of India from time to time with regard to the implementation of the Scheme and reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(xv) There shall be no appointment of permanent staff, except additional teachers only as per SSA norms. The existing staff of the State Government should be optimally utilized. The principal work of project implementation shall be on the mainstream administrative establishment at State and district levels. However, in case there is any need to appoint contractual staff for a limited period for the performance of specialised jobs for which expertise is not available with them. Such contractual staff may only be hired by the district/block/village levels only and the cost maintained within 6% management [illegible] as envisaged under the scheme.

(xvi) The guidelines issued by the Government of India from time to time regarding monitoring management and financial control and other procedure would be followed in the execution of the Project.

(xvii) The State Government should give a written commitment for meeting its share of the SSA/[illegible] lay.

(xviii) First [illegible] of the State share should also be released to the Society within one month [illegible] se of central share to the State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke [illegible] Parishad, Dehrudun, Uttarakhand.

(xix) Teac[illegible] against posts created through SSA funds should be made acco[illegible] for at least salary payment. The latter would monitor the atten[illegible] releasing the salary.

(xx) VEC[illegible] bodies should be constituted and accounts opened to incur expe[illegible] teachers grant, civil works, maintenance grants, school grants and othe[illegible] which has to be incurred only through these bodies as per SSA norm[illegible] within one month of its release.

(xxi) Sta[illegible] maintain their level of investment in elementary education as in 19[illegible] details of this to Government of India before the release of inst[illegible] contribution as State share for SSA will be over and above this inve[illegible]

(xxii) The [illegible], would only released after the previous installment of Sta[illegible] been transferred to the State Project Director, Uttarakhand Sa[illegible] Parishad, Dehrudun, Uttarakhand and substantial progress has bee[illegible] as far as money already released is concerned.

.../..

(xxiii) The grantee shall not entrust the implementation of the approved project to another organization and shall not divert the grant to the latter organization. The grant shall also not be utilized for purposes other than the one for which it is approved. Failure to do so will render the grantee liable to refund to the President of India, the sanctioned grant in full with interest @ 10% per annum thereon.

(xxiv) The accounts of all grantee Institutions or Organizations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act 1971 and Internal Audit by the Principle Accounts Officer of the Ministry of Department, whenever the Institution or Organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid.

(xxv) In case of non-recurring grant the Utilization Certificate should be submitted within 9 months of the closure of the financial year.

8. The expenditure will be debitable to Demand No. 58 Department of School Education and Literacy: Major Head 2202: General Education –01-Elementary Education -789- Special Component Plan for Scheduled Caste - 02- Sarva Shiksha Abhiyan - 02.01 General Component (CSS) - 02 1.31 Grant-in-aid General 2012-13 (Plan).

9. This sanction issues in exercise of the delegated powers and in consultation with Integrated Finance Division vide their Dy. No. 4515/2012/IFD dated 10.07.2012 and IF-II vide their Dy. No. 2012/IF-II dated.

10. The Grantee is located in the Uttarakhand Circle of Accounts.

11. No U.C. is pending in respect of the grantee Society.

Yours faithfully,

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23073542

Copy forwarded to:

1. State Project Director, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehrudun, Uttarakhand The grantee institution is required to submit the under mentioned documents as per terms and conditions of the sanction letter to enable the Ministry to release the grant:-

   (a) Bond for Rs.**4833 lakh** in revised format.
   (b) Authorisation letter as in the revised format.

2. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand , Dehradun.

3. The Principal Secretary (Education), Government of Uttarakhand, Sachicalaya, Dehradun-248001, Uttarakahnd. The State Government is requested to kindly furnish written commitment as per para 6 (vi) of the sanction.

4. The Drawing and disbursing Officer (Grants), Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy in duplicate for drawal and disbursement electronically.

5. Office of the Director General of Audit-I Central Revenue OAD-II Section, AGCR Building I.P. Estate, New Delhi 110002.

6. The Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.

7. The Accountant General, Uttarakhand, Dehradun

8. IF-2 Section/C. Unit/IFD/EE-15 section.

9. Shri Shalini Sharma, Chief Consultant TSG Ed-CIL New Delhi.

10. Guard File.

(Manjeet Kumar)
Under Secretary to the Government of India